● वर्ष-2
● अंक-150
रायपुर, शुक्रवार
10 फरवरी 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

इन दिनों

शशांक शर्मा

झीरम घाटी हत्याकांड की जांच पर जांच

देश की राजनीति में 25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस पार्टी के काफिले पर हुआ हमला अभूतपूर्व और ऐतिहासिक था। माओवादी के इस हमले में तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, महेन्द्र कर्मा सहित 28 नेता शहीद हो गए थे। इस घटना के तत्काल बाद डॉ रमन सरकार ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया था। इस बात को 10 वर्ष होने आए है लेकिन जांच पूरी नहीं हो सकी है और इसलिए इस हत्याकांड में शामिल हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। वैसे तो न्यायिक जांच के समानांतर तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए जांच भी शुरु कराई थी जिसने अपनी रिपोर्ट 2014 में दे दी थी। इस रिपोर्ट में घटना से संबंधित तथ्य और शामिल आरोपियों के नाम भी दर्ज है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एनआईए की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। उनका आरोप है कि एनआईए ने इस हत्याकांड की जांच में गंभीरता नहीं दिखाई और अनेक साक्ष्य और गवाहों पर गौर नहीं किया। दरअसल मामले की जांच तो एक विषय है लेकिन प्रदेश में झीरम घाटी कांड एक राजनीतिक विषय बनकर रह गया है। हत्याकांड के तत्काल बाद इसके पीछे की साजिशों को लेकर राजनेताओं पर भी उंगलियां उठीं। लेकिन कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ। तब से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झीरम घाटी का दोषी मानती है। एनआईए की रिपोर्ट को खारिज करने के बाद न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट भी नवम्बर 2021 में राजभवन को दे दी गई। आयोग ने 8 वर्षों तक सुनवाई करने साक्ष्य एकत्र करने के बाद 4,184 पृष्ठ की रिपोर्ट राज्यपाल अनुसुइया उइके को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार को आपत्ति थी और इस प्रक्रिया को परंपराओं के विरुद्ध बताते हुए नवम्बर 2021 को भूपेश सरकार ने एक नया जांच आयोग बिठा दिया जिसमें 2 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया। 11 नवम्बर को जारी आदेश में नए जांच आयोग के द्वारा 6 माह के भीतर जांच पूरी कर शासन को रिपोर्ट सौंपने की बात की गई थी। अब आयोग के गठन के बाद 6-6 माह के तीन कार्यकाल पूरे होने के आए, ऐसी स्थिति में शासन ने एक बार फिर इस जांच आयोग के कार्यकाल को अगस्त 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी झीरम घाटी के सच को बाहर लाने में क्या वाकई गंभीर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस और उनके नेता ऐसी रिपोर्ट चाहते है जो किसी दल या व्यक्ति के खिलाफ हो, ऐसा नहीं होने पर जांच पर जांच कराई जा रही है।

सड़क हादसा

सात छात्रों की मौत

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गुरुवार दोपहर सड़क हादसे में सात स्कूली बच्चों की मौत हो गई। सभी बच्चे एक ऑटो से स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चा और ऑटो चालक घायल हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें कांकेर रेफर कर दिया गया है। हादसा कोरर थाना क्षेत्र में हुआ है।

जानकारी के मुताबिक, स्कूल की छुट्टी होने के बाद आठ बच्चे एक ऑटो में सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान आयुष केंद्र, चिल्हटी चौक पर तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में मौके पर ही चार बच्चों तुरगहन निवासी रुद्रदेव (7) व रुद्राक्षी (6), बनौली निवासी ईसान मंडावी (4) और आसरा निवासी मानव साहू (6) की मौत हो गई। जबकि उपचार के दौरान तीन बच्चो ने दम तोड़ दिया। इनमें निशांत (8) और पीयूष (8) भी शामिल हैं। दोनों चचेरे भाई थे। ऑटो चालक सहित पांच बच्चे घायल हो गए। सभी बच्चे बीएसएनएन डिजिटल पब्लिक स्कूल के छात्र हैं। यह प्राइमरी क्लास में पढ़ते थे और सभी की उम्र चार से सात साल के बीच है। डॉक्टर अब चालक और एक अन्य बच्चे गौतम को रायपुर रेफर कर दिया है। दोनों की हालत गंभीर है।

सिंचाई विभाग के डिफाल्टरों को इनाम

नियमित सिंचाई कर अदा करने वालों को सजा, सिंचाई मंत्री को पुनः ज्ञापन

रायपुर। चुनावी घोषणापत्र में किये गये वादे को पूरा करने सिंचाई कर माफी संबंधी जारी किये गये जल संसाधन विभाग के आदेश ने 4 वर्षों का नियमित सिंचाई कर अदा करने वाले 90 प्रतिशत किसानों को सकते में डाल रखा है। वे इस आदेश को डिफाल्टरों को इनाम और नियमित सिंचाई कर अदा करने वाले किसानों को सजा ठहरा रहे हैं । इस संबंध में सन् 2021 में शासन का ध्यानाकर्षण कर इन 90 प्रतिशत किसानों से वसूल किये जा चुके राशि को आगामी वर्षों में समायोजित करने अथवा उन्हें लौटाने की मांग पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने व विभाग द्वारा सिंचाई कर वसूली की प्रक्रिया पुनः शुरू कर दिये जाने से एक बार फिर रायपुर जिला जल उपभोक्ता संस्था संघ ने सिंचाई मंत्री रवीन्द्र चौबे को मेल से ज्ञापन भेज व्यापक किसान हित में शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया है ।

रायपुर जिला जल उपभोक्ता संस्था संघ के अध्यक्ष रहे भूपेन्द्र शर्मा ने बंगोली सिंचाई उपसंभाग के सिंचाई पंचायतों के पूर्व अध्यक्षों की हुयी बैठक के बाद प्रेषित ज्ञापन में जानकारी दी है कि जल संसाधन विभाग द्वारा बकायादार किसानों का सिंचाई कर माफ कर दिये जाने संबंधी सन् 2021 के 3 मई को जारी आदेश से यह स्थिति उत्पन्न हुयी है ।

ज्ञापन में सिंचाई कर अदा करने संबंधी कानून का उल्लेख करते हुये जानकारी दी गयी है कि हरेक कृषि वर्ष में 15 मार्च तक सिंचाई कर अदा करना होता है और इसके बाद पेनाल्टी वसूल की जाती है । कृषि वर्ष सन् 2017 - 18 का सिंचाई कर इस तकनीकी आधार पर माफ न किये जाने कि वह बकाया की परिधि में नहीं आता की जानकारी देते हुये ज्ञापन में आगे बतलाया गया है कि सन् 2021 में बकायादार किसानों का सिंचाई कर माफ किये जाने संबंधी आदेश जारी होने के पूर्व ही प्रदेश के 90 प्रतिशत किसान कृषि वर्ष 2018 - 19 , 2019 - 20 व 2020 - 21 का सिंचाई कर या तो निर्धारित समयावधि में या फिर कालान्तर में पेनाल्टी सहित जमा कर चुके थे इस वजह से इस आदेश का लाभ सिर्फ उन रसूखदारों व प्रभावशाली किसानों को मिला जिनसे कर वसूल कर पाने की हिमाकत विभागीय अधिकारी नहीं कर पाते । ज्ञापन में इस संबंध में पूर्व में सन् 2021 के 11 अगस्त को सौंपे गये ज्ञापन की ओर ध्यानाकृष्ट कराते हुये लिखा गया है कि नियमित कर अदा कर चुके 90 प्रतिशत किसानों का राशि समायोजित करने अथवा वापस लौटाने संबंधी मांग अभी तक शासन के पास विचाराधीन रहने व विभागीय कमियों द्वारा सन् 2021 - 22 का राशि पेनाल्टी सहित व वर्तमान कृषि सत्र 2022 - 23 की राशि अदा करने दबाव बनाया जा रहा है जिसे कि समायोजित करने की स्थिति में अदा करने की जरूरत नियमित सिंचाई कर अदा करने वाले किसानों को नहीं पड़ता । इस संबंध में शीघ्र ही शासन से व्यापक किसान हित में निर्णय कराने का आग्रह श्री चौबे से किया गया है ।

श्री शर्मा ने जानकारी दी है कि इस संबंध में विचार करने आहूत बैठक में फरफौद सिंचाई पंचायत के अध्यक्ष रहे गोविंद चंद्राकर , मालीडीह से अध्यक्ष रहे हिरेश चंद्राकर , भानसोज से अध्यक्ष रहे थानसिह साहू , संडी से अध्यक्ष रहे प्रहलाद चंद्राकर , बोडरा से अध्यक्ष रहे धनीराम साहू , लखौली से अध्यक्ष रहे तुलाराम चंद्राकर , आरंग से अध्यक्ष रहे मनमोहन गुप्ता , भोथली से अध्यक्ष रहे भारतेन्दु साहू तथा फरहदा से अध्यक्ष रहे योगेश चंद्राकर सहित क्षेत्र के प्रबुद्ध किसान मौजूद थे ।

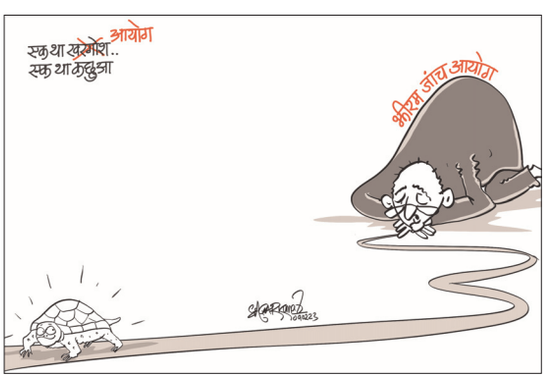

राजभवन ने कोर्ट के नोटिस के खिलाफ लगाया याचिका

आरक्षण विवाद और उलझा

बिलासपुर। आरक्षण विवाद में राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस के खिलाफ राजभवन हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट सचिवालय ने अपने खिलाफ जारी नोटिस पर याचिका लगाकर जारी हुए नोटिस पर अंतरिम राहत प्रदान करने की मांग की है। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

राज्य सरकार ने प्रदेश में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर 76 कर दिया है। 3 दिसंबर को विधानसभा से पास हुए आरक्षण संशोधन विधेयक को दस्तखत के लिए राजभवन भेजा गया था, पर राज्यपाल ने उस पर अब तक साइन नहीं किया है।

बिल पर 10 सवाल राज्यपाल ने पूछे थे, जिसके जवाब सरकार ने दे दिए हैं उसके बाद भी बिल पर दस्तखत नहीं करने को लेकर बिलासपुर के युवा अधिवक्ता हिमांग सलूजा व राज्य शासन ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर राज्यपाल को दस्तखत करने के लिए निर्देशित करने की मांग की थी। राज्य सरकार की ओर से देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा व अधिवक्ता हिमांग सलूजा की ओर से अधिवक्ता निर्मल शुक्ला व शैलेंद्र शुक्ला सुनवाई में पेश हुए थे। जिसमें अधिवक्ताओं ने तर्क देते हुए मांग की थी कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल को तय समय में ही या तो दस्तखत कर देना चाहिए या फिर वापस लौटा देना चाहिए। पर राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया है।

बहस के दौरान बताया गया कि यदि विधेयक को राज्यपाल को साइन नहीं करना था तो उसे राष्ट्रपति के पास भेज देना था। पर राज्यपाल को भी राष्ट्रपति ने विधेयक को नहीं भेजा है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस भेजकर 2 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

राजभवन ने अपने खिलाफ जारी नोटिस पर अंतरिम राहत हेतु हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में राजभवन को पक्षकार बनाने व हाई कोर्ट के द्वारा टस जारी करने को चुनौती दी गई थी। आज जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। राजभवन की ओर से पूर्व अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल और सीबीआई व एनआईए के विशेष लोक अभियोजक बी गोपाकुमार प्रस्तुत हुए। वही राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा पेश हुए।

प्रमुख समाचार

कोर्ट की निगरानी में हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग, शीर्ष अदालत में सुनवाई कल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए राजी हो गया है। याचिका में रिपोर्ट की जांच शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट इसके लिए केंद्र सरकार को एक समिति गठित करने का निर्देश दे। याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता विशाल तिवारी ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। उन्होंने पीठ को बताया कि इस मुद्दे पर दायर एक अलग याचिका को 10 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना है। उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि अलग याचिका के साथ उनकी याचिका पर भी शुक्रवार को सुनवाई की जाए। पीठ में न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला भी शामिल हैं।

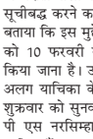

बिहार में जातिगत सर्वेक्षण से बढ़ गई हिंसा, केंद्र से टीम भेजने का आग्रह-रूडी

नई दिल्ली/पटना। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने गुरुवार को दावा किया कि बिहार के सारण जिले में हाल ही में दो युवाओं की हत्या में जाति एक कारक है। उन्होंने सवाल किया कि क्या राज्य सरकार यह देखने के लिए पानी का परीक्षण कर रही है कि क्या जाति का टकराव उसकी राजनीति के लिए अच्छा है। उन्होंने केंद्र से जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए एक टीम भेजने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने वहां इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। रूडी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि दोनों युवक जाति से किए गए घावों के शिकार हुए हैं। सारण के सांसद ने कहा, क्या बिहार की राज्य सरकार सारण के छपरा में परीक्षण कर यह देखने की कोशिश कर रही है कि क्या जातिगत भेदभाव में वृद्धि उसकी राजनीति के लिए पर्याप्त है? इसके लिए गहन जांच की जरूरत है। घटना स्थल उनके निर्वाचन क्षेत्र के पड़ोस में है। उन्होंने कहा कि उन्हें चिंता इस बात की है कि राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए जाति सर्वेक्षण के बाद हिंसा करीब आ गई है।

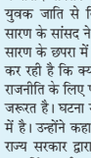

मोदी की यूनिवर्सिटी डिग्री का मामला, गुजरात हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) द्वारा दायर याचिका से संबंधित एक मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया था। सॉलिसिटर जनरल ने एचसी को बताया छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है! हालांकि डिग्री सार्वजनिक डोमेन में है। आरटीआई के तहत किसी तीसरे व्यक्ति को प्रति देने की कोई बाध्यता नहीं है। बता दें कि केजरीवाल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता का विवरण सार्वजनिक करने के लिए सीआईसी को एक पत्र लिखा था। केजरीवाल ने पत्र में कहा कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए डिग्री को सार्वजनिक डोमेन में लाया जाना चाहिए।

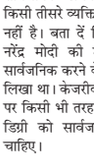

चंडीगढ़ हिंसा मामले में पुलिस का खुलासा, प्रदर्शनकारी बैरिकेड और टियर गैस गन लूट ले गए

चंडीगढ़। चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर बुधवार को हिंसक झड़प हुई थी। चंडीगढ़ पुलिस ने बुधवार को हुई हिंसक झड़प में सात नेताओं समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जिन नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है उनमें गुरचरण सिंह, बलविंदर सिंह, लोक अधिकार लहर, अमर सिंह चहल, दिलशेर सिंह जंडियाला, जसविंदर सिंह राजपुरा, रुपिंदर जीत सिंह व अज्ञात शामिल हैं। इन सभी पर 17 विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इनमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आर्म्स एक्ट समेत कई धाराएं हैं। एफआईआर में लिखा है कि प्रदर्शनकारियों के हमला करने के बाद महिला व पुरुष पुलिस कर्मचारियों ने भाग कर अपनी जान बचाई। यदि वह ऐसा नहीं करते तो प्रदर्शनकारी उन्हें जान से मार देते। पुलिस ने लिखा है कि प्रदर्शनकारियों ने उनके 20 बैरिकेड, वज्र गाड़ी में से टियर गैस एंड गन, पुलिस की अन्य गाड़ियों में से काफी सारा सामान अन्य हथियारों को लूट लिया है।

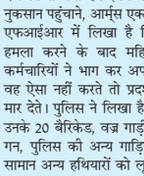

महिलाओं को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की अनुमति

नई दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि धार्मिक ग्रंथों, सिद्धांतों और मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में प्रवेश करने की अनुमति है, बशर्ते कि सामान्य क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं का स्वतंत्र रूप से मिलना-जुलना न हो। हलफनामे में बताया गया है कि किसी भी मस्जिद में महिला-पुरुषों का आपस में मुलाकात का जिक्र नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के लिए एक कम्फर्टेबल और सुरक्षित जगह उपलब्ध है, जहां वे शांति से नमाज अदा कर सकती हैं। हलफनामे में कहा गया है कि जब मक्का में काबा के आसपास नमाज अदा करने की बात आती है, तो नमाज के दौरान पुरुषों और महिलाओं के उपासकों के बीच अलगाव प्रदान करने के लिए बैरिकेड्स लगाकर अस्थायी व्यवस्था की जाती है। प्रार्थना के शिष्टाचार, विशेष रूप से दोनों लिंगों का मुक्त अंत:क्रिया नहीं। सभी नमाजियों द्वारा स्वेच्छा से, सख्ती से और ईमानदारी से पालन किया जाता है, चाहे पुरुष हों या महिलाएं। हलफनामे में कहा गया है कि वास्तव में, मक्का में मस्जिद अल-हरम के बगल में सैकड़ों मस्जिदें हैं, जहां पैगंबर मुहम्मद के समय से जेंडर के परस्पर संबंध की अनुमति नहीं है।

दक्षिण भारत की 60 सीटों पर भाजपा की नजर

हरीश गुप्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकल्पनीय और बड़ा जोखिम लेने के लिए जाने जाते हैं. उन्हें अपने फैसलों से सभी को चौंका देने की आदत है. अगर सत्ता के गलियारों में दिग्गजों की मानें तो मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण से चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं. यह दांव अगर चला जाता है तो इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर भाजपा के लिए दरवाजे खोलना है.

भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पीएम ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उन्हें एक रोडमैप देने के लिए कहा कि कैसे पार्टी पांच दक्षिणी राज्यों से 60 लोकसभा सीटें जीत सकती है. वर्तमान में, भाजपा का कर्नाटक में मजबूत आधार है, जहां उसने 2019 के लोकसभा चुनावों में 28 में से 25 सीटें जीतीं और तेलंगाना में 17 में से 4 सीटें जीतीं. लेकिन आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में उसे एक भी सीट नहीं मिली. भाजपा आलाकमान इन राज्यों में अपना आधार मजबूत कर रहा है और तेलंगाना की अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश में है. मोदी दक्षिण में पार्टी के आधार का विस्तार करने की अपनी योजनाओं के बारे में भाजपा नेतृत्व से जवाब तलब करते रहे हैं. केरल में, यह एक लंबा रास्ता है लेकिन तमिलनाडु राडार पर है, ध्यान आकर्षित करने वाले सुझावों में से एक यह है कि पीएम को उनके वर्तमान वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के अलावा तमिलनाडु से भी खड़ा करना फायदेमंद होगा.

तमिलनाडु पर नजर -भाजपा का दक्षिण प्रवास मोदी को तमिलनाडु के रामनाथपुरम लोकसभा क्षेत्र में ले जा सकता है. भाजपा नेतृत्व जानता है कि वह हिंदी पट्टी, पश्चिम और उत्तर पूर्व में लगभग सैच्युरेशन प्वाइंट पर पहुंच गया है. इसलिए, इसे दक्षिण को जीतने के लिए अकल्पनीय कदम उठाने होंगे. एक आईपीएस अधिकारी को हिंदुत्व के एजेंडा के साथ तमिलनाडु भाजपा की कमान सौंपी गई. नवंबर, 2022 में महीने भर चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के बीच के संबंध को फिर से खोजना था. महीने भर चलने वाले इस

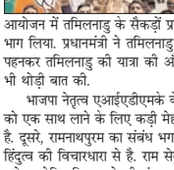

आयोजन में तमिलनाडु के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया. प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की पोशाक पहनकर तमिलनाडु की यात्रा की और तमिल में भी थोड़ी बात की.

भाजपा नेतृत्व एआईएडीएमके के दोनों धड़ों को एक साथ लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है. दूसरे, रामनाथपुरम का संबंध भगवान राम से, हिंदुत्व की विचारधारा से है. राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने की संभावना है जिसका मामला फिलहाल अदालत में है. अड़चन एक ही है; क्या पीएम को दो सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए और इससे यूपी के मतदाताओं को क्या संकेत जाएगा जहां भाजपा 75 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतना चाहती है. इस मुद्दे पर फैसला होना बाकी है. रहस्य तभी खुलेगा जब चुनाव आयोग 2024 में 8 चरणों में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा.

राज्यसभा की दो खाली सीटों पर निगाहें- राज्यसभा के लिए मनोनीत सांसदों की 12 सीटों में से दो सीटें करीब एक साल से खाली पड़ी हैं. सरकार ने पिछले साल 5 हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामांकित किया था और उनमें से हर पसंद पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच का संकेत देती है. महान एथलीट पीटी उषा को केरल से चुना गया, तो भारतीय परोपकारी डॉ. वीरेंद्र हेगड़े को कर्नाटक से चुना गया. तमिलनाडु से संगीत उस्ताद इलैयाराजा और आंध्र से पटकथा लेखक और निर्देशक वी. विजेंद्र को चुना गया. चारों दक्षिणी राज्यों से हैं. इसके अलावा, मोदी ने जम्मू- कश्मीर के एक एसटी नेता गुलाम अली को भी नामित किया. लेकिन इनमें से कोई भी भाजपा में शामिल नहीं हुआ, जैसा कि अतीत में सोनल मानसिंह और अन्य मनोनीत सांसदों के मामले में हुआ था. पता चला है कि शेष दो नामांकन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि चुनावी राज्यों से हो सकते हैं. पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची पर एक नजर डालने से पता चलता है कि दक्षिण भारत पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

गहलोत को राहत- जहां भाजपा आलाकमान ने नवंबर-दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राहत दी है, वहीं कांग्रेस ने भी आखिरकार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बदलने की अपनी योजना छोड़ दी है. चौहान को बदलने के लिए चुनावी वर्ष की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम ओबीसी नेता को खोजने में भाजपा असमर्थ रही है. उधर राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही तीखी लड़ाई का हल निकालने की भरपूर कोशिश की. लेकिन तीनों नेताओं के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक पूरी तरह से विफल रही. सचिन पायलट को अकेला छोड़ दिया गया है.

मोदी ने ओडिशा के लिए क्यों खोला खजाना- पीएम मोदी की डिक्शनरी में बेवजह कुछ भी नहीं है. जब मोदी ने अश्विनी वैष्णव को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और उन्हें तीन प्रमुख विभाग दिए, तो इसका श्रेय ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया गया जिन्होंने राज्यसभा में उनके प्रवेश की सुविधा प्रदान की. लेकिन यह इतिहास की बात है और रिश्ते ने तब एक कड़वा मोड़ ले लिया जब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं की एक रैली में 'बीजद-मुक्त' ओडिशा बनाने का आह्वान किया. न तो मोदी और न ही वैष्णव ने नवीन पटनायक के खिलाफ एक शब्द बोला है. इसके विपरीत, पूर्व आईएएस अधिकारी, जो कटक और बालासोर में जिला कलेक्टर थे, ने रेलवे परियोजनाओं के लिए राज्य द्वारा मांगी गई राशि से अधिक धन आवंटित किया. मोदी ने ओडिशा के लिए केंद्र का खजाना खोल दिया, जिसने 8,400 करोड़ रुपए की मांग की थी लेकिन मोदी ने 2023-24 के लिए 10,012 करोड़ रुपए दिए।

श्रमिकों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले: ताम्रध्वज साहू

■ **श्रमिक पंजीयन की गति बढ़ाने पर दिया जोर, 637 हितग्राहियों को 1 करोड़ 17 लाख 98 हज़ार का चेक वितरण हुआ**

दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक मजदूरों को दिलाने के लिए श्रमिक पंजीयन पर जोर दिया जाना आवश्यक हैश्रम विभाग के अधिकारीयों को जिले में शिविर लगाकर अधिकाधिक श्रमिकों का पंजीयन करने के निर्देश उक्त बातें प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने ग्राम खम्हरिया में श्रम विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में कहा।इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम खम्हरिया में पटेल भवन में लोकार्पण 1.50 लाख रूपये की राशि से आहता एवम शौचलय निमार्ण , भूमिपूजन खेल मैदान में 5 लाख की राशि से तार एवं पेंशिंग कार्य , सीसी सड़क राशि 8.80 लाख का भूमिपूजन किया गया।इस कार्यक्रम में मुख्याअतिथि प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू , अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष शालनी रिवेंद्र यादव, विशेष अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी महामंत्री जितेन्द्र , कृषिसभा पति योगिता चंद्राकार, जनपद उपाध्यक्ष झमित गायकवाड़,जनपद सदस्य राकेश हिरवानी,सरपंच

सुखी राम यादव,रोशन साहू पूर्व सरपंच कोकड़ी,दिनेश पटेल उपस्थित थे। कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहि शालनी रिवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अगुवाई में समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। आज राज्य उन्नाति की ओर अग्रसर हो रहा है और नए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं।

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत ग्राम खम्हरिया में छत्तीसगढ़ भवन एवम अन्य सन्निर्मण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में चेक वितरण हितग्राहीओ किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत लाभांवित संख्या 407 वितरण राशि 8160000 रूपये।मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत संख्या 95 बच्चो को 568000 रूपये का चेक प्रदान किया गया।मिनिमता महतारी जतन योजना के अंतर्गत 127 हितग्राहियों को 2,540000 रूपये का चेक प्रदान किया गया।निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2 लाभार्थी को 100000 रूपये का चेक प्रदान किया गया।मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना 2 लोगो को 30000 रूपये का चेक प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत 400000रूपये की राशि का चेक प्रदान हितग्राहियों को किया गया। इस अवसर पर उप सरपंच खुमान पटेल,राजीव युवा मितान क्लब अध्यक्ष द्रोपती साहू , बलराम चंद्राकार, शेषणारायण पटेल,लोकनाथ साहू,फुलसिंग साहू,शंकर साहू,निखिल निषाद,हीरालाल साहू,मुन्ना चंद्राकार सहित श्रम विभाग से श्रम निरीक्षक एल आर यदु, श्रद्धा वर्मा,रमन मांडवी,मंजूषा ,प्रशांत एवं ग्रामीण जन बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

सरगुजा के आंगनबाड़ी केंद्रों में लगे ताले

नियमितिकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल

अंबिकापुर। चुनावी वर्ष के शुरू में ही कांग्रेस सरकार पर वादों को अमल में लाने का दबाव बनाने कर्मचारी संगठन लामबंद होने लगे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस द्वारा जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है।

सरगुजा जिले में कल से आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लटक जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का एक संगठन पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहा है। अब दूसरे संगठन ने भी नौ फरवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने का निर्णय ले लिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के दो संगठनों के हड़ताल पर चले जाने से महिला बाल विकास विभाग की सारी गतिविधियां कल से सरगुजा जिले में ठप हो जाएंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार से लेकर टीकाकरण का काम भी बाधित हो जाएगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर सरगुजा जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ भी नौ फरवरी से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बंद कर जिला, परियोजना और ब्लाक स्तर पर धरना, प्रदर्शन करेंगे।आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं का एक संगठन पहले से ही अंबिकापुर के भारतीय स्टेट बैंक कलेक्टोरेट के पास धरना प्रदर्शन कर रहा है। इस संगठन के आंदोलन से कई आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लग चुके हैं। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ द्वारा भी कल नौ फरवरी से आठ सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन करने से महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं का संचालन पूरी तरह से ठप हो जाने की संभावना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ,सहायिका संघ सरगुजा की महामंत्री फुलासो एक्का ने बताया कि 14 फरवरी 2022 से मांगों के समर्थन में अनिश्चित कालीन हड़ताल किया गया था। उस दौरान महिला बाल विकास मंत्री से मिले आश्वासन के बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया था लेकिन शासन स्तर से अभी तक मांगों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका नौ फरवरी से केंद्रों का संचालन बंद कर धरना देंगे।संघ की प्रमुख मांगों में आंगनबाड़ी कर्मियों को शासकीय कर्मचारी घोषित कर सामाजिक सुरक्षा देखकर उन्हें उचित श्रेणी में शामिल करने की है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं होने तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन 18 हजार तथा सहायिका को नौ हजार प्रतिमाह भुगतान करने सहित आठ सूत्रीय मांग रखी गई है। पोषण ट्रैकर में कार्य करने हेतु एंड्रॉयड फोन, सिम, इंटरनेट खर्च की राशि का भुगतान करने की भी मांग की गई है।

हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में महिलाओं का घर घर दस्तक

■ **नगर पालिक निगम रिसाली के विभिन्न वार्डों में पहुंच रहे कार्यकर्ता**

रिसाली। नगर पॉलिक निगम रिसाली के विबिन्न वार्डो में हाथ से हाथ जोड़ो की प्रभारी श्रीमती सरिता साहू के नेतृत्व विभिन्न वार्डो में पहुँच रहे है। छग के काँग्रेस सरकार की योजनाओ व कार्यो को घर घर दस्तक देकर बता रहे है। जिससे आम नागरिकों में काफी जागरूकता आ रहा है।इसी कार्यक्रम के तहत 7 फरवरी को वार्ड क्रमाक 5 नगर पालिका निगम रिसाली मे हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा सम्पन्न हुआ। कॉंग्रेस नेताओ कार्यकर्ताओ ने वार्ड का भ्रमण कर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के द्वारा किये गये विकास कार्यों की जानकारी दी.गई । इस हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा में ब्लॉक प्रभारी श्रीमती सरिता जितेंद्र साहू के मार्गदर्शन मे सतत यात्रा जारी है। इस यात्रा में प्रमुख रूप से ब्लाक अध्यक्ष मुकुंद भाउ महामंत्री चंद्रकांत कोरे व नगर पालिका निगम रिसाली की महापौर श्रीमती शशी सिन्हा महापौर परिषद के सदस्य गण श अनुप डे चंद्रभान सिंह ठाकुर सोनिया देवांगन चंद्र प्रकाश निगम सिंग गोविंद चतुर्वेदी ईशवरी साहू पार्षद विनय नेताम श्रीमती सारिका साहू श्रीमती रेखा देवी श्रीमती ममता यादव रोहित धनकर एलडरमेन श्रीमती संगीता सिंग श्रीमती संध्या वर्मा मो. निजाम सीसीर साहू तरुण बंजारे जी श्रीमती अनुपमा गोस्वामी जयंती महानंद शेष जांगड़े अनिता साहू सोलमा मुर्मू सोना प्रसाद पुष्प लता देशमुख पार्वती मैत्रा प्रियंका गौतम अवधेश यादव जाकीर अहमद

नरेश कोठारी राजेंद्र रजक गोविंद वर्मा शुभम वर्मा सुरेंद्र बाघमारे जी मनीष बारहेन पुष्प कली राज पेनुक नेताम प्रेमचंद साहू शमशेर आलम अशोक सिन्हा लझमीकांत साहू गजेंद्र देवांगन रितेश सिंग रामा भाषकर शशि कांत दुबे लोमन सोनी जी उबारन टंडन लोकूमल ओतवानी दिपांकर साहू राजेंद्र वर्मा प्रमोद चौधरी राहील खान अजय मिश्रा अमन दीप सोढ़ी सहित अन्य महिलाये व कार्यकर्ता शामिल हुई।

कुकरेल क्षेत्र में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा में शामिल हुई सिहावा विधायक

नगरी। सिहावा विधायक डॉ.लक्ष्मी ध्रुव के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुकरेल के तमाम पदाधिकारियों की उपस्थिति में हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा ग्राम पंचायत सियारीनाला के अंतर्गत गुडरापारा, जामनाला, बीजापुर में क्षेत्र की माताएं, युवा साथियों एवं बुजुर्ग जन के साथ गांव की गलियों में आम जनों से हाथ से हाथ जोड़कर केंद्र की भाजपा सरकार की नाकामियों बढ़ती महंगाई, रोजगारी के संबंध में आम जनता के समक्ष रखा। साथ ही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। पदयात्रा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुकरेल के अध्यक्ष अखिलेश दुबे, विधायक प्रतिनिधि नारद ध्रुव, जोन अध्यक्ष सोहनलाल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष करण चंद्राकर, जनपद सदस्य सुश्री पुष्पा ध्रुव, श्रीमती संतोषी साहू, शुरूज लाल कुंजाम, राजीव मितान युवा मितान क्लब के अध्यक्ष, सियारीनाला की सरपंच सहित कांग्रेस जन उपस्थित थे। हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सियारीनाला में संकुल स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। संकुल स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं एवं शिक्षक बंधुओं द्वारा विधायक महोदया का स्वागत सम्मान किया गया।

अमलेश्वर में हाथ मे हाथ जोड़ो यात्रा सम्पन्न

पाटन। नगर पालिका परिषद अमलेशवर मे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान का समापन मे मुख्यमंत्री के पुत्र चैतन्य बघेल, (बिट्टू) मुख्यमंत्री के ओ एस डी. आशीष वर्मा , मंडी बोर्ड अध्यक्ष अश्वनी साहू,ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र वर्मा, अफेक्स बैंक डायरेक्ट राकेश ठाकुर, जनपद उपाध्यक्ष देवेंद्र चंद्रवंशी, अन्य पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष संजय यदु , शालिक साहू, नीरज सोनी, नगर पालिका अध्यक्ष कु. नंदनी पठारी, धर्मेंद्र साहू, जीवनंदन वर्मा विष्णु यादव, अमृत सिंह राजपूत, खिलेशवर चक्रधारी, नेमप्रकाश भारती, द्रोपति निषाद, गंगा प्रसाद निषाद, ममता नाग, ओंकार घिडोड़े, हिमांशु शर्मा, नरेंद्र त्रिपाठी,कल्याण साहू, ईश्वरी सोनकर, रूपनारायण दुलारी बाई साहू,सोनकर,सीतल सोनकर,एवं नवनिर्वाचित पार्षद, विकास वर्मा, महेद्र साहू, घनश्याम साहू, पुनीत साहू, गिरधर साहू, गोविंदा निषाद,किरण चंद्राकर,दिनेश वर्मा,किशोर निषाद, सुमित ठाकुर, धनेश्वर साहू कुशान वर्मा,,घनश्याम चेलक, मोहन सिगौर, बसंत सिंगौर,जित्तू पटेल,टेकराम साहू, राजा चंद्राकर, तोरण साहू, नेतराम यदु, हिंछा राम साहू,कृष्णा साहू, भरत राजपूत, विशाल सिंह राजपूत,थानु साहू,सुनील सिंह राजपूत, वीरेंद्र साहू, रोशन साहू, डोमन साहू, सुन्नी साहू,सत्तू कौशल,टेकु साहू, डब्बू साहू,रवि साहू,घनश्याम यादव,डालू निषाद

शंकराचार्य ने रेखचंद जैन को दिया यशस्वी और विजयी होने का आशीर्वाद

■ **संसदीय सचिव के निवास में किया गया स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की चरण पादुका का पूजन**

जगदलपुर। पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने संसदीय सचिव एवं विधायक रेखचंद जैन को यशस्वी और पुन: विजयी होने का आशीर्वाद दिया है। शंकराचार्य के श्रीचरण बुधवार को श्री जैन के जगदलपुर स्थित निवास में पड़े थे। रेखचंद जैन, उनकी धर्मपत्नी संगीता जैन एवं अन्य परिजनों ने शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज की चरण पादुका का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने एक समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन द्वारा किए जा रहे जनसेवा के कार्यों और जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए समर्पण की प्रशंसा की। स्वामी जी ने कहा - राजधर्म यही संदेश देता है कि स्वार्थ त्याग कर प्रजा और पशु पक्षियों की सेवा करें, प्रजा के लिए स्वच्छ शुद्ध पानी, चिकित्सा, बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था करें, राजा, उसके मंत्री, सह मंत्री और उसके कर्मचारी प्रजा के कष्ट को अपना कष्ट मानकर उसके निवारण करें। शंकराचार्य ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार, मुख्यमंत्री और आप (रेखचंद जैन) निश्चय ही जनसेवक के रूप में काम कर रहे हैं। देश को आज ऐसे ही सेवभावी जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है। जिस दिन से सभी जनप्रतिनिधि आपकी तरह सेवा भावना के साथ कर्तव्य निर्वहन करने लग जाएंगे, उस दिन से भारत का प्राचीन वैभव पुर्नस्थापित होने लग जाएगा। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने रेखचंद जैन को यशस्वी और पुन: विजयी होकर जनसेवा करते रहने के लिए आशीर्वाद दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक, कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्त्ता उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

हाथियों की दहशत से 30 गांवों के स्कूल बंद

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ शहर के नजदीक हाथियों का दल पहुंचने से आसपास के गांवों में दहशत मची है। इसी बीच हाथियों के झुंड का जायजा लेने के लिए राजधानी रायपुर से एडिशनल PCCF कौशलेंद्र कुमार बिलासपुर पहुंचे। वहीं APCCF कुमार ने हाथी सम्बंधित गाइड लाइन का पालन करने के दिए निर्देश। सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के 30 गांवों के स्कूलों को बंद कराया गया है। गांवों में लाइट बंद रखने के निर्देश भी दिए गए, ताकि हाथियों का झुंड आसानी से आगे बढ़ सके। सोंठी परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 51 व 53 में हाथियों का दल हाथी विचरण कर रहा है। विभाग ने 100 से अधिक वनकर्मियों को मौके पर तैनात किया है। वनकर्मियों के मुताबिक सुबह से शाम तक आराम करते गजराज नज़र आए और अंधेरा होने पर आसपास विचरण किए। कोरबा शहर के नजदीक हरदीबाजार के रेकी के पास भ्री विचरण करते एक दर्जन हाथियों के झुंड और 6 नन्हें शावकों को ग्रामीणों ने देखा। इससे इलाके में खौफ का माहौल है।

खनिज के अवैध उत्खनन पर की जाए सख्त कार्यवाही

कोरबा। कलेक्टर संजीव झा ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभा कक्ष में खनिजों के अवैध उत्खनन-परिवहन की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण पर की गई कार्यवाही की जानकारी ली। साथ ही टास्क फोर्स समिति के सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एसईसीएल खनन क्षेत्र में कोयला की चोरी की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु एसईसीएल प्रबंधन को निर्देशित किया। साथ ही खनिज परिवहन में संलग्न वाहनों को तारपोलिन से ढंककर व्यवस्थित रूप से परिवहन करने हेतु निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने खनन क्षेत्र का मासिक प्रतिवेदन/कर निर्धारण समयावधि में करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा जिले में संचालित निर्माण विभागों में फ्लाई एश ब्रिक्स का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए समस्त निर्माण विभाग को आवश्यक निर्देश दिए।

बर्ड फ्लू की दहशत, तीन दिन में 3700 मुर्गियों की मौत

बालोद। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बर्थ फ्लू की दहशत ने दस्तक दी है। इस बार बालोद में तीन दिन के अंदर 3700 मुर्गियों की मौत हो गई। यह मुर्गियां एक ही फार्म पर थीं। पशुपालन विभाग को इसका पता भी तीसरे दिन चला। इसके बाद टीम पहुंची और शेष मरी हुई मुर्गियों का सैंपल लेने के बाद उन्हें दफना दिया गया है। जांच के लिए सैंपल को रायपुर भेजा गया है। हालांकि विभाग को आशंका है कि मुर्गियों में कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक, दल्लीराजहरा के वार्ड-16 में तिवारी पोल्ट्री फार्म है। इस फार्म से मुर्गियों की मौत का सिलसिला तीन दिन पहले शुरू हुआ था। पहले दिन 300, फिर अगले दिन 600 मुर्गियों की मौत हो गई। इस पर फार्म संचालक ने बिना पशुपालन विभाग को सूचना दिए, उन्हें दफना दिया। तीसरे दिन सभी मुर्गियां मर गईं। इसकी जानकारी जब मंगलवार को पशु पालन विभाग को लगी तो अफसर मौके पर पहुंच गए। इसके बाद टीम ने मुर्गियों का पोस्टमार्टम कराया और उन्हें दफनाने से पहले सैंपल लिए गए। उन्हें जांच के लिए भेजा गया है।

लोक कला महोत्सव में सीएम के ओएसडी शामिल हुए

पाटन। छत्तीसगढ़ी लोक कला महोत्सव का आयोजन महका खुर्द मे किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आशीष वर्मा ओएसडी मुख्यमंत्री थे। अध्यक्षता सुरेंद्र गायकवाड अध्यक्ष सरपंच संघ पाटन ने की। गांव में हुए विकास कार्यो पर प्रकाश डालते हुए नेमचंद निर्मलकर ने मुख्यमंत्री एवं सभी अतिथियों का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए गांव के मांग को अतिथियों के समक्ष रखा गया। आभार प्रदर्शन सरपंच सुरेंद्र गायकवाड के द्वारा व्यक्त किया गया। इस लोक कला महोत्सव में छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक कला दल के लगभग 500 कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। जिसमें प्रथम दिवस हृदय शालिनी मानस परिवार मटंग (सांतरा) जिला दुर्ग, जय मारादेव मारिया जस झांकी मंडली पचपेड़ी (भखारा) जिला धमतरी, दिया के अंजोर फाग झांकी मंडली पेंड्री (कलंगपुर)जिला बालोद , सत्य के पुजारी सतनाम बाल बालिका पंथी पार्टी महका खुर्द (उतई) जिला दुर्ग आदि विधाओं की नयनाभिराम प्रस्तुति हुआ।

मंत्री लखमा ने स्कूली बच्चों से की बातचीत

दंतेवाड़ा। प्रदेश के वाणिज्य कर आबकारी एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान भैरमबंद ग्राम के स्कूली बच्चों को अपने पास बुलाकर उनसे आत्मीय बातचीत की। इस दौरान मंत्री लखमा ने इन स्कूली बच्चों रिषभ, अनुराग, और सुजाता से उनके स्कूल में संचालित गतिविधियों, स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता आदि के बारे में पूछा। मंत्री ने इन बच्चों से पूछा कि आगे भविष्य में क्या बनना चाहते हो, जिस पर एक छात्र ने शिक्षक, एक ने फोटोग्राफर और सुजाता ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कलेक्टर बनने की इच्छा जताई। जिस पर मंत्री लखमा ने खुश होकर ताली बजाई और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मंत्री लखमा ने हाईस्कूल जा रही कक्षा 9वीं की छात्राए कुमारी पूजा, दिव्या और ज्योति से भी चर्चा की। छात्राओं ने बताया कि वे गांव से 5 किलोमीटर दूर स्कूल जा रही हैं, जिस पर मंत्री लखमा ने इन छात्राओं को शासन द्वारा सायकल दिये जाने की जानकारी ली।

छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति अत्यंत समृद्ध है : तारा साहू

■ **कला मरती नहीं बल्कि अमर बना देती है**

नवापारा राजिम। माघी पुन्नी मेला में रंगतरंग लोककला मंच रायपुर की लोकगायिका सुश्री तारा साहू ने मीडिया सेंटर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति अत्यंत समृद्ध हैं। मेरे घर में संगीत का कोई माहौल नहीं था स्कूलों में सहपाठी के साथ मिलकर गीत गाती थी, जिसे सुनकर शिक्षक शाबासी देते थे। धीरे-धीरे रूझान बढ़ता गया और रामायण, जगराता, भजन संध्या जैसे कार्यक्रम में जाकर प्रस्तुति देने लगी। इस दौरान कई लोग भला-बूरा कहते रहे, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए जैसे-जैसे अवसर मिलते रहा आगे बढ़ता

रही। कला मेरे लिए वरदान है सन् 2006 में लोककला मंच दूज के चँदा से जुड़ी सन् 2010 में प्रसिद्ध लोक गायिका सीमा कौशिक के साथ मंच साझा किया। उससे मुझे जो खुशी मिलनी थी नहीं मिल पायी।

उन्होंने कहा कि पैसे कमाने के लिए खूब मेहनत करना है तमन्ना थी कि इसी पैसे से अपने लिए स्कूटी खरीदूँ। बी.ए. तक पढ़ाई कर अभी खैरागढ़ विश्वविद्यालय से लोककला में डिप्लोमा कर रही हूँ। जॉब करके सपना पूरा करना मुश्किल था क्योकिं जो दिखता है वह बिकता है। इसलिए प्रतिदिन खूब मेहनत करती रही । लोक गायिका के साथ मैं एक्ट्रेस भी हूँ। छत्तीसगढ़ी फिल्म तिरीया के चक्कर, बाप बड़े न भैया सबसे बड़ा रूपईया जैसे दर्जनों फिल्मों पर काम कि हूँ। मेरी इच्छा है कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को लेकर बहुत आगे तक जाऊँ। अभी तक 800 से ज्यादा मंचों में प्रस्तुति कर चुकी हूँ। भोरमदेव महोत्सव, मैनपाट महोत्सव, सिरपुर महोत्सव, राज्योत्सव के अलावा पिछले साल राजिम माघी पुन्नी मेला मे प्रस्तुति देना यादगार क्षण रहा।पिछले वर्ष आधे घण्टे में दो घण्टा का कार्यक्रम परोसना था। प्रारम्भ होने में मात्र 20 मिनट शेष था। मंच मे कलाकार बैठने के लिए पहुँच चुके थे। लेकिन संगीत पक्ष के आर्गन प्लेयर नहीं आये थे। समापन दिवस था। गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या मे उपस्थित थे। स्थिति-परिस्थिति को देखकर मैं खूब रोई परन्तु हिम्मत नहीं हारी। अचानक चमत्कार देखने मिला और आर्गन बजाने वाला मिल गया। आधे घण्टे में छतीसगढ़ी बारह मासी गीत एवं जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारित गीत प्रस्तुति ने खूब वाहवाही लुटी। राजिम महोत्सव में यह मेरा दूसरा कार्यक्रम है। तारा साहू ने आगे बताया कि जीवन में उथल-पुथल लगा रहता है इसका मतलब घबराने कि जरूरत नहीं। सुख और दुख दोनों आते हैं, कर्म करते रहें समय आने पर फल जरूर मिलेगा। क्योंकि कला मरती नहीं बल्कि अमर बना देती है।

अनियमित विकास का नियमितीकरण न कराने पर होगी मकान, दुकान सील

कोरबा। अनियमित विकास का नियमितीकरण न कराने पर अनियमित रूप से बनाए गए मकान, दुकान आदि को सील करने की कार्यवाही शीघ्र ही निगम द्वारा की जाएगी, वहीं इसे अवैध निर्माण मानकर तोड़ा भी जा सकता है। वहीं निगम के बड़े बकायादारों तथा बकाया की अंशिक राशि जमा कर शेष राशि जमा न करने वालों पर भी सीलिंग व कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। आज आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने निगम अधिकारियों की बैठक लेकर नियमितीकरण व राजस्व वसूली कार्य की समीक्षा करते हुए उक्ताशय के निर्देश अधिकारियों को दिए। नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने अधिकारियों की बैठक लेकर अनियमित विकास के नियमितीकरण व राजस्व वसूली की कार्यप्रगति के साथ-साथ शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन व निगम के विभिन्न कार्यो की कार्यप्रगति की बिन्दुवार समीक्षा की। आयुक्त पाण्डेय ने अनियमित विकास के नियमितीकरण हेतु सर्वेक्षण कार्य एवं प्राप्त आवेदनों तथा उन पर की गई कार्यवाही की जोनवार समीक्षा की, उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वे एवं नोटिस दिए जाने के बाद संबंधितों द्वारा नियमितीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं या नहीं, इस पर फोकस करते हुए आवेदन पत्रों को जमा कराएं, अनियमित विकास व निर्माण का शत प्रतिशत नियमितीकरण हो तथा अनियमित निर्माण करने वाले सभी व्यक्ति नियमितीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करें, इस दिशा में विशेष अभियान के रूप में कार्यवाही संपादित कराएं, लोगों को प्रेरित करें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

गृहमंत्री अमित शाह 25 को बिहार दौरे पर रहेंगे

नईदिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस बार अमित शाह एक ही दिन में दो अलग-अलग जिलों में सभा को संबोधित करेंगे। पटना में किसान मजदूर समागम तो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिहार में बदले सियासी समीकरण के बाद अब भाजपा के निशाने पर जदयू की सीटें हैं। वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट पर दो दशक से अधिक एनडीए का कब्जा रहा है। अब भाजपा इस सीट को जदयू से छीनने के लिए पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां अब तैयारी तेज कर चुकी है। एक ओर जहां महागठबंधन अपनी तैयारी में है तो वहीं भाजपा अब आक्रमक होकर इस ओर जुट रही है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। इस बार वो 25 फरवरी को वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र पहुंच रहे हैं। इस सीट को जदयू से छीनने के प्रयास में भाजपा लगेगी।

दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने की 8वीं गिरफ्तारी

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की आबकारी नीति में आठवीं गिरफ्तारी की है। ईडी ने कथित 'अनियमितताओं' से जुड़े धन शोधन के मामले में विज्ञापन के पेशे से जुड़े राजेश जोशी को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि जोशी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। गोवा विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर 'रिश्वत' लेने-देने के संबंध में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में दाखिल किए अपने दूसरे आरोपपत्र में दावा किया है कि दिल्ली की अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति में कथित रूप से ली गई 100 करोड़ रुपये की 'रिश्वत' के एक हिस्से का इस्तेमाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के अभियान में किया गया। ईडी मामले में अभी तक जोशी सहित आठ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

सीएम केजरीवाल के घर के बाहर भाजपा का प्रदर्शन

नई दिल्ली। फीडबैक यूनिट (एफबीयू) को लेकर भाजपा गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली सरकार राजनीतिक विरोधियों के प्रति दुर्भावना से काम करती है, उनके दमन में विश्वास करती है। दमन के उद्देश्य से ही 1 फरवरी 2016 को केजरीवाल सरकार ने एफबीयू का गठन किया, ताकि राजनीतिक विरोधियों, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, उपराज्यपाल कार्यालय, मीडिया हाउस, प्रमुख व्यापारियों ही नहीं न्यायाधीशों तक पर नजर रखी जा सके। उपराज्यपाल अविलंब इस संदर्भ में सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दें। सचदेवा ने कहा कि अराजक परिपाटी के कारण केजरीवाल सरकार ने एफबीयू की स्थापना अपने कैबिनेट की स्वीकृति के आधार पर कर दी।

त्रिपुरा में भाजपा ने जारी किया घोषणा-पत्र

अगरतला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। इस दौरान अगरतला में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि त्रिपुरा कभी नाकाबंदी और उग्रवाद के लिए जाना जाता था। राज्य अब शांति, समृद्धि और विकास के लिए जाना जाता है। त्रिपुरा में अब तक 13 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड दिए गए हैं, जिसमें सेटलमेंट में 107 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि जब बीजेपी संकल्प पत्र लेकर आती है, तो यह एक विजन डॉक्यूमेंट होता है, यह केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, यह लोगों के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अब हम एक त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा, उन्नत त्रिपुरा की ओर बढ़ रहे हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि जो कहा था, वो किया है। 2018 त्रिपुरा के लिए निकास द्वार और प्रवेश द्वार दोनों साबित हुआ है।

नगालैंड में 200 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र पाये गये वैध

कोहिमा। निर्वाचन आयोग ने नगालैंड विधानसभा चुनावों के लिये नामांकन पत्रों की जांच के बाद 222 आवेदनों में से 200 को अवैध पाया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 225 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था जिनमें से तीन बाद में चुनाव मैदान से हट गये थे। उन्होंने बताया कि जिन 200 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाये गये उनमें चार महिलाएं हैं। सत्तारूढ़ नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी), भारतीय जनता पार्टी, नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ), कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी), जनता दल यूनाइटेड, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) राइजिंग पीपुल्स पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत 13 दलों ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। बीस से अधिक निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख शुक्रवार है।

राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा

जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही खिलेगा : मोदी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कल खरगे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार-बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, मैं आता हूं, वह तो आपने देखा, लेकिन आप यह भी देखें कि वहां 1 करोड़ 70 लाख जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। सिर्फ कलबुर्गी में ही 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं।

राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसे देखकर उनकी (मल्लिकार्जुन खरगे) पीड़ा मैं समझ सकता हूं। आप दलित की बात करते हैं यह भी देखें कि उसी जगह दलित को चुनाव में जीत भी मिली। अब आपको जनता ही नकार दे रही है तो आप उसका रोना यहां रो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह सदन राज्यों का सदन है बीते दशकों में अनेक बुद्धिजीवियों ने सदन से देश को दिशा दी। सदन में ऐसे लोग भी बैठे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कई सिद्धियां प्राप्त की है। सदन में होने वाली बातों को देश गंभीरता से सुनता और अनुसरण करता है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन में कुछ लोगों का व्यवहार और वाणी न सिर्फ सदन को बल्कि देश को निराश करने वाली है। माननीय सदस्यों को मैं कहूंगा कि कीचड़ उसके पास था मेरे पास गुलाब... जो भी जिसके पास था, उसने दिया उछाल। जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ज्यादा खिलेगा।

मोदी ने कांग्रेस को लेकर विपक्ष को किया सचेत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। उन्होंने, कांग्रेस को लेकर विपक्ष को भी सचेत कर दिया। साथ ही पीएम ने इशारों इशारों में पुरानी पेंशन पर बड़ी बात कही। वे बोले, ऐसा पाप न करें, जो आपके बच्चों का अधिकार छीन ले। उन्होंने आर्थिक संकट में फंसे एक पड़ोसी मुल्क का उदाहरण भी दिया। कुछ राज्य आज उसी राह पर चल रहे हैं। वे तत्कालीन भुगतान के चक्कर में देश को बर्बाद कर देंगे। अपने फैसलों के द्वारा वे आने वाली

पीढ़ियों पर भारी बोझ डाल रहे हैं। सदन में पीएम के संबोधन के दौरान जब कांग्रेस एवं दूसरे विपक्षी दल, मोदी-अदाणी के नारे लगा रहे थे, तो उन्होंने विपक्ष को लेकर कई उदाहरण दे डाले। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किस तरह से विपक्षी दलों की सरकारें गिराई थीं, उसके बारे में बताया। पीएम ने सदन में मौजूद शरद पवार का नाम लेकर कहा, ये युवा मुख्यमंत्री थे, मगर कांग्रेस ने उनकी सरकार भी गिरा दी।

कांग्रेस गिराती है सरकारें

पीएम मोदी ने कहा, जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने अपनी सरकार में राज्यों के अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी थीं। मैं कच्चा-चिट्ठा खोलना चाहता हूं। वो लोग कौन थे, जिन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। पीएम मोदी ने कहा, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार प्रयोग किया, वह नाम है इंदिरा गांधी। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे। कुछ ही दिनों में चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। डीएमके के मित्रों को भी बताता हूं। तमिलनाडु में भी एमजीआर और करुणानिधि जैसे दिग्गजों की कई सरकारों को कांग्रेस वालों ने गिरा दिया। एनजीओ की आत्मा देखती होगी, आप कहां खड़े हो। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में भी ऐसा ही किया था। वहां विपक्ष की सरकार को नहीं चलने दिया। राजभवनों को कांग्रेस का दफ्तर बना दिया गया था।

आने वाली पीढ़ियों पर भार है पुरानी पेंशन

पीएम ने पुरानी पेंशन लागू करने वाले राज्यों को सचेत करते हुए कहा, यह आने वाली पीढ़ियों पर भार है। वे इससे बचें। देश और राज्य की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करें। ऐसा पाप न करें, जो उनके बच्चों का अधिकार छीन ले। यह चिंता का विषय है। राज्यों को अनुशासन का रास्ता चुनना होगा। अगर वे ऐसा करते हैं, तो हमें भी उनका भला करने में सुविधा हो जाएगी। केंद्र उन्हें लाभ पहुंचाना चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा, 600 से ज्यादा योजनाएं गांधी-नेहरू के परिवार के नाम पर हैं। अगर किसी कार्यक्रम में नेहरू जी का नाम नहीं प्रयोग हुआ, तो कुछ लोगों का खून गर्म हो जाता था। आज उनकी पीढ़ी नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखती है। हिंदुस्तान, आज डिजिटल दुनिया का लीडर बना हुआ है। एक समय था, जब हम मोबाइल फोन का आयात करते थे, आज मेरा देश मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। दवाइयां पहुंचाने का काम ड्रोन से हो रहा है। इसके लिए हमने ड्रोन पॉलिसी में बदलाव किया है।

राजनीतिक खेल खेलने वाले बचने का रास्ता ढूंढ रहे

अपने भाषण के आखिर में विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि देश की जनता की रोजी रोटी के लिए हमने काम किया। 140 करोड़ लोगों के लिए हमारी सरकार काम कर ही है। देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी लोग बदलने पड़ रहे हैं। मैं घंटेभर से जवाब दे रहा हूं, रुका नहीं रहा। देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हूं। इसलिए राजनीतिक खेल खेलने वालों के अंदर अंदर हौसला नहीं है। वे बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं।

इससे पहले पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर विपक्ष आइना दिखाया। उन्होंने कहा पिछले कुछ वर्षों में 27 लाख करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से सीधा हितधारकों के खातों में गए हैं। इससे 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक रुपया... जो किसी इको-सिस्टम के हाथों में जा सकता था, वो बच गया। अब जिनको ये पैसा नहीं मिल पाया, उनका चिल्लाना स्वाभाविक है।

मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से हटाए गए शब्द, कांग्रेस ने जताई आपत्ति

विपक्षी कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण के कुछ हिस्सों को आधिकारिक रिकॉर्ड से हटाने पर आपत्ति जताई। पार्टी ने दावा किया कि उन्होंने किसी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों का इस्तेमाल पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया था। हालांकि, धनखड़ ने समीक्षा से इनकार करते हुए कहा कि वह पहले ही फैसला कर चुके हैं।

राज्यसभा में दिन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस सांसद बुधवार को की गई टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाने के औचित्य पर सवाल उठा रहे थे, जबकि इसी तरह की टिप्पणियां पूर्व प्रधानमंत्रियों वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने सदन में की थीं और जो कार्यवाही का हिस्सा बनी हुई हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा?

वहीं, मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि बजट सत्र की शुरुआत में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार सदन में कही गई बातों को सदन की कार्यवाही से नहीं हटाया जा सकता।

खरगे ने कहा, मैंने न तो किसी असंसदीय शब्द या भाषा का इस्तेमाल किया और न ही किसी पर कोई आरोप लगाया। फिर भी आप कुछ शब्द चुनकर निकाल देते हैं ... मैं यह नहीं कहूंगा कि आपने उनकी गलत व्याख्या की, लेकिन अगर आपको कोई संदेह था तो आप एक अलग तरीके से स्पष्टीकरण मांग सकते थे। इसके बजाय भाषण के छह अलग-अलग हिस्सों को हटा दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा, ये वही शब्द हैं जिनका इस्तेमाल सदन में पहले भी किया गया था। वाजपेयी ने (पूर्व प्रधानमंत्री) पीवी नरसिम्हा राव के लिए भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया था। यह अभी भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप इसे देख सकते हैं।

जयराम कोई मुद्दा उठाते हैं, उसे काट दिया जाता है : खरगे

उन्होंने कहा कि जब जयराम रमेश सहित पार्टी के नेता कोई मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें काटकर छोटा कर दिया जाता है। उन्होंने कहा, आप कहते हैं कि यह सही नहीं है... आप बैठ जाओ... आपको पढ़ाई करनी चाहिए। रमेश ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है और उन्हें हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी आती है। वह संसदीय भाषा जानते हैं और फिर भी आप उन्हें टोकते रहते हैं। यह सही नहीं है। उन्होंने सभापति धनखड़ से रिकॉर्ड देखने को कहा। जब खरगे ने जब कहा कि जो भी उनके बचाव में आता है, उसे कुर्सी से रोका जाता है, इस पर धनखड़ ने कहा कि सभापति विपक्ष के नेता के अंतिम रक्षक हैं। खरगे ने पलटवार करते हुए कहा, लेकिन वही तो नहीं हो रहा है। आप हटा रहे हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

पहले दिन का खेल खत्म ऑस्ट्रेलिया 100 रनों से आगे

नागपुर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 177 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट पर 77 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया 100 रन आगे और भारत के नौ विकेट बचे हुए हैं। कप्तान रोहित अर्धशतक लगाकर खेल रहे हैं। उनके साथ अश्विन भी नाबाद है।

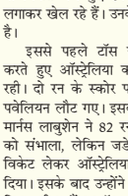

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। दो रन के स्कोर पर टीम के दोनों ओपनर पवेलियन लौट गए। इसके बाद स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन ने 82 रन की साझेदारी कर टीम को संभाला, लेकिन जडेजा ने एक ओवर में दो विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट में ठकेल दिया। इसके बाद उन्होंने स्मिथ को भी आउट कर दिया। पीटर हैंड्सकॉम्ब और एलेक्स कैरी ने भी अर्धशतकीय साझेदारी की, लेकिन अश्विन ने इस जोड़ी को तोड़ा। इसके बाद उन्होंने जडेजा के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी 177 रन पर खत्म कर दी। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 49 रन मार्नस लाबुशेन ने बनाए। उनके अलावा स्टीव स्मिथ 37, एलेक्स कैरी 36 और पीटर हैंड्सकॉम्ब 31 ही दहाई का आंकड़ा छू सके। भारत के लिए जडेजा ने पांच विकेट लिए। उन्होंने टेस्ट में 11वीं बार ओवर में पांच विकेट लेने का कारनामा किया। वहीं, अश्विन ने तीन विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने टेस्ट में अपने 450 विकेट भी पूरे किए। शमी और सिराज को एक-एक विकेट मिला। सिर्फ अक्षर पटेल कोई विकेट नहीं ले सके।

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में आक्रामक शुरुआत की। 76 रन के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरा है। लोकेश राहुल 71 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हुए।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 142 अंक चढ़ा निफ्टी 17900 के नीचे

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन मजबूती दिखी। वायदा कारोबार के वीकली एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर बंद होने में सफल रहे। सेंसेक्स 142 अंकों की मजबूती के साथ 60,806 और निफ्टी 21 अंक चढ़कर 17893 के लेवल पर बंद हुआ। बाजार में सबसे ज्यादा कमजोरी मेटल सेक्टर के शेयरों में दिखी। निफ्टी के मेटल इंडेक्स में 1.5 फीसदी की गिरावट आई। अदाणी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर भी 11% तक लुढ़के हैं। वहीं दूसरी ओर आईटी और फाइनेंस सेक्टर के शेयरों में मजबूती दिखी है। निफ्टी के टॉप गेनर्स शेयरों में बजाज फिनसर्व और हिंडाल्कों में दो-दो प्रतिशत की बढ़त आई। आईआरसीटीसी के शेयर अच्छे नतीजों के बाद 1.5% के ऊपर बंद हुए। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार एक्सचेंज में 3613 शेयरों का लेन-देन किया गया।

भारत में लॉन्च हुई ट्विटर पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस

नई दिल्ली। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफार्म ट्विटर ने आखिरकार भारत में अपनी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्विटर ब्लू को लॉन्च कर दिया है। भारत में ब्लू टिक लेने और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस के फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल यूजर्स को 900 रुपये प्रतिमाह चुकाने होंगे। वहीं कंपनी ने 650 रुपये में सबसे कम कीमत वाला प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान जारी किया है। यह प्लान वेब यूजर्स के लिए है। कंपनी के अनुसार, भुगतान करके सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को एडिट ट्वीट बटन, 1080p वीडियो अपलोड, रीडर मोड और ब्लू टिक की सुविधा मिलेगी। कंपनी ने अपने पुराने वेरिफिकेशन प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। कंपनी के अनुसार, पुराने ब्लू टिक अकाउंट होल्डर्स को अपने ब्लू टिक को बनाए रखने के लिए कुछ महीनों की छूट दी जाएगी।

बीवाईडी भारत में जल्द करेगी इलेक्ट्रिक सेडान कार को लांच

नई दिल्ली। बीवाईडी की ओर से भारतीय बाजार में जल्द ही पहली इलेक्ट्रिक सेडान कार सील को लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले कंपनी की ओर से इस कार की जानकारी को अपनी वेबसाइट पर साझा कर दिया गया है। कंपनी ने इस सेडान कार को इससे पहले ऑटो एक्सपो 2023 में भी शोकेस किया था। तब कंपनी की ओर से कार की जानकारी को साझा नहीं किया गया था। जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक कार की मोटर काफी ताकतवर होगी। इसके जरिए कार को सिर्फ 3.8 सेकेंड में जीरो से 100 किलोमीटर की रफ्तार तक ले जाया जा सकेगा। कंपनी की ओर से 83.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर इसका मूज टेस्ट भी किया गया है। कंपनी ने इसमें 82 किलोवॉट की बैटरी दी है। जिससे कार को सिंगल चार्ज में करीब 700 किलोमीटर तक चलाया जा सकेगा।

ग्लोबल मार्केट में ईंधन सस्ता हुआ तो देश में घटेंगी एलपीजी कीमतें

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमत 750 डॉलर प्रति मीट्रिक टन से नीचे आती है तो घरेलू एलपीजी को और भी किफायती दरों पर बेचा जा सकता है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, अंतरराष्ट्रीय कीमत कई कारकों से तय होती है और मैंने जो विश्लेषण पढ़ा उसमें से एक में कहा गया है कि कुछ साल में यह सब बीते जमाने की बात हो जाएगी क्योंकि तक काफी मात्रा में गैस उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा, लेकिन हमें अगले दो या तीन साल वर्तमान जैसी वैश्विक स्थिति से गुजरना होगा पर चीजें बेहतर हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री उन सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे जिसमें पूछा गया था कि घरेलू गैस सिलेंडरों की लागत कम क्यों नहीं की जा रही है।

बजट में सार्वजनिक निवेश पर जोर कायम

डॉ संजय बारू

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार की बजट रणनीति को बरकरार रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट में भी आर्थिक वृद्धि के संचालक के तौर पर सार्वजनिक निवेश पर अपना फोकस कायम रखा है। इसका व्यापक रूप से स्वागत हुआ है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े दिखाते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सकल सावधि पूंजी निर्माण की हिस्सेदारी 2008 से लगातार घट रही है।

वर्ष 2007 में यह 36 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था, जो 2020 में 22 प्रतिशत हो गया। यह रुझान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की चुनौती के केंद्र में है। बीते एक दशक की औसत सालाना वृद्धि 2000-15 की औसत वृद्धि 7.15 प्रतिशत से कम रही है। उससे पहले यह आंकड़ा 1950-80 में 3.15, 1980-2000 में 5.15 और 2003-10 में आठ प्रतिशत से अधिक रहा था।

मोदी सरकार के दौर में वृद्धि दर प्रभावी नहीं रही है। बीते नौ वर्षों में सालाना औसत दर लगभग छह प्रतिशत और 2019-22 में तीन प्रतिशत रही है। अगर अगले दशक को 'अमृत काल' होना है, तो दर को 7-8 प्रतिशत के स्तर पर लाना होगा। इस सरकार के पहले कार्यकाल में समुचित निजी निवेश नहीं होने पर उसे आकर्षित करने के लिए पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुछ कर छूट दिया था।

जेटली ने वित्तीय क्षेत्र की साफ-सफाई के लिए भी अनेक कदम उठाये थे। तभी अर्थव्यवस्था पर पहले नोटबंदी और फिर कोरोना महामारी का प्रहार हुआ। अनिश्चितता में कम मांग और निजी क्षेत्र का जोखिम लेने में हिचक जैसे कारक भी जुड़ गये। इसके फलस्वरूप 2019-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर महज तीन प्रतिशत के आसपास रही। फरवरी, 2022 में

सीतारमण ने उस विचार, जिसे अर्थशास्त्री 'नव-उदारवाद' कहते हैं, के एक महत्वपूर्ण मंत्र को त्याग कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की।

वह मंत्र यह था कि सार्वजनिक निवेश निजी निवेश को हाशिये पर डाल देता है। उस समय वित्त मंत्री का भाषण लिखने वालों ने नेहरू युग के अर्थशास्त्र की इस समझ को खोज निकाला कि सार्वजनिक निवेश से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। पचास के दशक में भारत की विकास रणनीति इसी समझ पर आधारित थी। तब समुचित संसाधनों का अभाव निजी निवेश में बाधक था, पर वर्तमान दशक में कई तरह के कारक- आर्थिक एवं राजनीतिक- निजी निवेश की राह रोक रहे हैं।

वित्त मंत्री ने पूंजी व्यय बढ़ाने की नयी रणनीति, जिसे मैंने 'कैपिटल स्ट्राइक' कहा है, इस आशा में अपनायी है कि इससे मांग बढ़ेगी और निजी निवेश प्रोत्साहित होगा। इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई है और 2022-23 में अर्थव्यवस्था की बेहतरी में इसका योगदान रहा है। पर इस बेहतरी के साथ बहुत अधिक मुद्रास्फीति भी रही है। पिछले साल बजट के तुरंत बाद यूक्रेन पर रूस के हमले से कीमतें बढ़ीं और निवेशक हतोत्साहित हुए।

मुद्रास्फीति नियंत्रित करना और आर्थिक वृद्धि की अपेक्षाएं बढ़ाना इस साल वित्त मंत्री के लिए चुनौती हैं। इसके लिए उन्होंने राजस्व खर्च घटाने, वित्तीय घाटे पर गंभीरता बरतने जैसे उपाय अपनाया है। उन्होंने पूंजी व्यय बढ़ाया है ताकि आय वृद्धि की उच्च दर बनी रहे। रिजर्व बैंक ने भी मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के प्रयास में भागीदारी की है।

इस संतुलित प्रयास की प्रशंसा हुई है क्योंकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखते हुए निवेश चक्र को बढ़ाना आय, रोजगार, मांग और राजस्व वृद्धि के लिए आवश्यक है। आलोचकों ने रेखांकित किया है कि अगर बजट के वित्तीय आवंटन को सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी खर्च के साथ जोड़ा जाए, तो कुल पूंजी खर्च में मामूली वृद्धि ही हुई है।

आकलनों के अनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में वृद्धि को सार्वजनिक क्षेत्र निवेश को घटाकर संतुलित किया गया है। इससे निर्माण में वृद्धि प्रभावित हो सकती है क्योंकि अधिकांश सार्वजनिक निवेश निर्माण में ही है। जवाहरलाल नेहरू की तमाम आलोचना करने के बावजूद भाजपा सरकार आर्थिक और विदेश नीति में नेहरू के रास्ते पर चल रही है।

जम्मू-कश्मीर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

गौतम मोरारका

जम्मू-कश्मीर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्या शुरू हुई, गुपकार गैंग के नेताओं और जम्मू-कश्मीर को बरसों तक अंधेरे में रखने वाले नेताओं को अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिल गया है। गुपकार गैंग के फारूख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हों या महबूबा मुफ्ती या फिर अपनी नई पार्टी बना कर जम्मू-कश्मीर में उसकी सियासी जड़ें जमाने में जुटे गुलाम नबी आजाद जैसे नेता, यह सभी जनता को भ्रमित करने और प्रशासन की ओर से चलाई जा रही मुहिम के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। बुलडोजर चलता देख महबूबा मुफ्ती को लग रहा है कि कश्मीर अफगानिस्तान बनता जा रहा है तो उमर अब्दुल्ला कथित रूप से अपने करीबी लोगों के खिलाफ कार्रवाई से भड़क गये हैं। वहीं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी (डीएपी) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद भी जम्मू कश्मीर प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं और जनता को भड़का रहे हैं। भड़काते भड़काते वह यहां तक कह गये कि यदि मकान और छोटी दुकानें गिरायी गयीं तो हड़ताल एवं पथराव की संस्कृति की वापसी हो सकती है।

हम आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजादी ने कहा है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान से भ्रष्टाचार हो रहा है क्योंकि लोग यह सुनिश्चित करने के लिए राजस्व अधिकारियों को रिश्वत दे रहे हैं कि उनके नाम उन लोगों की सूची में नहीं आये जिन्होंने सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया है। गुलाम नबी आजाद ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को गरीब लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देने का आश्वासन देने को लेकर धन्यवाद दिया, लेकिन मांग की है कि त्रस्त लोगों को राहत देने के लिए सरकारी आदेश जारी किया जाना चाहिए।

वहीं दूसरी ओर, महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुँची हुई हैं जहां एक दिन पहले वह राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर उतरीं। महबूबा मुफ्ती संसद तक मार्च करने के इरादे से बोट क्लब इलाके में पहुंचीं थीं जहां उनके दर्जनों समर्थक एकत्र हुए थे। उनके हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर लिखा था, डराना-धमकाना बंद करो, 'स्टॉप बुलडोजिंग' (इमारतें ध्वस्त करना बंद करो)। पीडीपी प्रमुख जम्मू-कश्मीर में चलायी जा रही ''बुलडोजर नीति'' से विपक्षी दलों को अवगत कराना चाहती थीं। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को हिरासत में ले लिया तथा उन्हें और उनके समर्थकों को जंतर मंतर पर ले गयी। इसके बाद, प्रदर्शनकारी वहां से चले गये।

उधर, जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि किसी भी गरीब का घर नहीं उजाड़ा जायेगा और जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि यह आश्वासन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया है। उधर, प्रशासन की इस मुहिम को जनसमर्थन भी बढ़ता जा रहा है। प्रवासी कश्मीरी पंडितों के एक संगठन ने सरकारी जमीन को वापस लेने के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान का स्वागत किया है तथा इस केंद्रशासित प्रदेश में अलगाववाद को प्रोत्साहित करने में नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की भूमिका की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने की मांग की है। दूसरी ओर, श्रीनगर में नेशनल कांफ्रेंस के समर्थकों ने प्रेस इंक्लेव इलाके में प्रदर्शन कर बुलडोजर कार्रवाई को रोकने की मांग की। प्रभासाक्षी संवाददाता ने जब इन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि किसी भी कार्रवाई से पहले प्रशासन की ओर से नोटिस नहीं दिया जा रहा है जोकि गलत है।

नया भारत में युवाओं की भागीदारी

ललित गर्ग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवावस्था में अपनी डायरी के पन्नों पर 'न्यू इंडिया' और 'युवा भारत' का जो सपना शब्दों में पिरोया था, वह आज साकार होता नजर आ रहा है। भारत मजबूती से लगातार नई पहल के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से भारत ने मोदी के नेतृत्व में चुनौतियों का सामना किया है, वह अपने आप में काबिले तारीफ है। यह निश्चित है कि मोदी के नेतृत्व में एक नई सभ्यता और एक नई संस्कृति गढ़ी जा रही है। नये विचारों, नये इंसानी रिश्तों, नये सामाजिक संगठनों, नये रीति-रिवाजों और नयी जिंदगी की हवायें लिए हुए आजाद मुल्क की गाथा सुनाता भारत एक बड़ा सवाल लेकर भी खड़ा है कि हम अपनी बुनियाद यानी युवाओं के सपनों को कब पंख लगायेंगे? कब उनकी निराशा की बदलियों की धूंध को दूर करेंगे? देश की युवा पीढ़ी की जरूरतों को कब पूरा करेंगे एवं कब उन्हें परेशानियों से मुक्त करेंगे? यह एक बड़ा सवाल है।

कहते हैं कि युवा देश की धड़कन ही नहीं, उसके भविष्य का नियामक और नियंता भी होता है। स्वामी विवेकानंद ने जिस युवा पीढ़ी की ऊर्जा और राष्ट्रीय चरित्र की बात कही थी, वह आज बिखरी-सी क्यों नजर आ रही है? केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 15 साल में 100 में से 77 लोग बूढ़े होंगे। सतत विकास के एजेंडे की बात करें, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सन 2030 तक युवा रोजगार के अवसरों एवं शिक्षा-प्रशिक्षण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि भारत की बात करें, तो देश की युवा पीढ़ी के लिए सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यदि व्यक्तित्व में कर्मठता और ईमानदारी के साथ-साथ जिम्मेदारी का अहसास भी हो तो, किसी भी सेक्टर की नौकरी के प्रति अति आकर्षण कोई बुरी बात नहीं है। नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि आज सपने देखना और आकांक्षाओं को उड़ान देना, यही युवा की पहचान होती है। फिर ऐसे क्या कारण हैं कि भारत का युवा कुछ विलक्षण, अद्भुत एवं अनूठा करने की बजाय नौकरी तक ही उलझा है?

कभी अमेरिका के वर्जीनिया में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को अमेरिका बनाकर दिखाने का संकल्प व्यक्त किया था। बहत्तर वर्ष के मोदी का अपनी इसी जिन्दगी में ऐसा करने का विश्वास व्यक्त करना कहीं अतिश्योक्ति तो नहीं है? लेकिन बड़े सपने हमें वहां तक नहीं तो उसके आसपास तो पहुंचा ही देते हैं, इसलिये मोदी के इस संकल्प को सकारात्मक नजरिये से ही देखा जाना देश के हित में है। उन्होंने बड़ा सपने लिया और उन्हें पूरा भी किया। लेकिन इन सुनहरे सपनों के बीच का यथार्थ बड़ा डरावना एवं बेचैनियों भरा है। देश की युवापीढ़ी बेचैन है, परेशान है, आकांक्षी है और उसके सपने लगातार टूट रहे हैं। देश का व्यापार धराशायी है, आम जनता अब शंका करने लगी है। इन हालातों में नया भारत बनाना या उसे अमेरिका बनाकर दिखाना एक बड़ी चुनौती है।

विकसित देशों में युवा 20 साल का होते-होते अपने स्वयं के इनोवेशन के लिए काम करने लगता है। बार-बार फेल होकर भी वह सफलता की ऊंचाई छूने की कोशिश में लगा रहता है। मगर भारत के हालात अलग हैं। कितना हास्यास्पद है कि हमने कुछ सरकारी नौकरियों को इतना महिमामंडित कर दिया है कि हर व्यक्ति वही नौकरी करना चाहता है, जिसमें दबंगई हो, प्रतिष्ठा हो, जी-हजूरी करने वालों की फौज हो, सुविधावाद हो। विकास को आकार देने में जुटे समाज में दबंगई की जरूरत ही क्या है। उधर उच्च शिक्षण संस्थान पढ़ाई की बजाय राजनीति के केंद्र बन रहे हैं। राजनीति बुरी नहीं, मगर आलम यह है कि वहां ऐसे नेता नजर आते हैं, जिनका पढ़ाई से कोई लेना-देना नहीं है। वे समय-समय पर बस अपनी ताकत ही दिखाते रहते हैं। हमने आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया और अब भी हम अपने युवाओं को पुरानी मानसिकता से बाहर निकालकर रिसर्च और इनोवेशन के लिए तैयार ही नहीं कर पा रहे। चीन और जापान की तरह उन्हें उत्पादक नहीं बना पा रहे हैं। भारत नया बनने के लिए, स्वर्णिम बनने के लिए, अनूठा बनने के लिए और उसे अमेरिका बनाकर दिखाने के लिये अतीत का बहुत बड़ा बोझा हम पर है। बेशक हम नये शहर बनाने, नई सड़कें बनाने, नये कल-कारखानें खोलने, नई तकनीक लाने, नई शासन-व्यवस्था बनाने के लिए तत्पर हैं लेकिन मूल प्रश्न है इनमें युवाओं की भागीदारी कब सुनिश्चित करेंगे और कब हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे? भारत में आबादी का छठा हिस्सा बेरोजगार है और हम वैश्वीकरण की ओर जा रहे हैं, अमेरिका बनने की सोच रहे हैं, नया भारत बना रहे हैं। यह खोखलापन है। बहुत आवश्यक है संतुलित विकास की अवधारणा बने। केवल एक ही हाथ की मुट्ठी भरी हुई नहीं हो। दोनों मुट्ठियां भरी हों। वरना न हम नया भारत बना पायेंगे और न हम अमेरिका जैसा बन पायेंगे।

अमृत महोत्सव का माहौल है। अमृत काल है, जो हमें पीछे मुड़कर देखते हुए भविष्य के सपने बुनने के लिये पुनरावलोकन की मांग करता है कि हमें पहुंचना कहां था और हम जा किधर रहे हैं? सवाल उठता है कि भारत की धीमी प्रगति का एक कारण कहीं सरकारी नौकरी के प्रति युवाओं का अति लगाव, सरकारी तंत्र का भ्रष्टाचार में लिप्त होने के साथ-साथ कामकाज की तुलना में अधिक तनख्वाह एवं सुविधाएं देना तो नहीं है? आजादी के 75 साल बाद भी 92 प्रतिशत युवाओं में खतरों को मौल लेने की क्षमता ही नहीं विकसित हो पाई। आखिर वे सिर्फ सरकारी अथवा गैर सरकारी नौकरी से चिपक कर अपना जीवनयापन क्यों करना चाहते हैं? यह बात सच है कि बिना खतरे उठाए सफलता की ऊंचाई प्राप्त नहीं की जा सकती, नया भारत नहीं बनाया जा सकता। ऐसा लगता है कि देश का अधिकांश युवा वर्ग बिना पानी में उतरे तैरने का चैंपियन बनना चाहता है। विकास के बड़े और लुभावने सपनों के साथ-साथ हम विवेक को कायम रखें, नैतिक मूल्यों एवं मौलिक सृजन को जीवन का आधार बनाएं। जिस प्रकार गांधीजी ने 'मेरे सपनों का भारत' पुस्तक लिखी, उन्होंने अपने सपनों में हिन्दुस्तान का एक प्रारूप प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने गरीबी, धार्मिक संघर्ष, अस्पृश्यता, नशे की प्रवृत्ति, मिलावट, रिश्वतखोरी, शोषण, दहेज और वोटों की खरीद-फरोख्त को विकास के नाम विध्वंस का कारण माना। उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के नाम पर भौतिकवाद, सुविधावाद और अपसंस्कारों का जो समावेश हिन्दुस्तानी जीवनशैली में हुआ है उसे उन्होंने हिमालयी भूल के रूप में व्यक्त किया है। लगता है हमने युवा हाथों में विकास के सपने थमाने की बजाय सुविधावाद थमा दिया।

विदेशों में भारत की स्थिति को मजबूत बनाना अच्छी बात है, लेकिन देश में बदलते हालातों पर निगाह एवं नियंत्रित भी जरूरी है। ऐसा नहीं होने का ही परिणाम है कि आठ सालों से लगातार युवा पीढ़ी निराशाओं से घिरती जा रही है। उनको नजरअंदाज करने की ही निष्पत्तियां कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सिर उठा रही हैं। जो युवा मोदीजी को वोट देता गया, जिताता गया। अब वही पूछने लगा है कि क्या हुआ हमारे सपनों का? नया भारत हमारी बेचैनियों पर कैसे खड़ा करोगे? युवा वर्ग को जिम्मेदार और जुझारू बनाने के साथ हर तरह के नशे से बचाने के ठोस प्रयास आवश्यक हैं, ताकि परिवार, समाज और देश का भी भविष्य खतरे में न पड़े और युवाओं की भागीदारी से भारत सचमुच नया भारत एवं सशक्त भारत बने।

प्रसंग — मुक्ति का मूल्य

महाराज बिम्सिार को नींद नहीं आ रही थी। तीर्थ कार महावीर ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि उन्हें नरक में जाना पड़ेगा। नरक की कल्पना से ही वे कांप उठे। उन्होंने सोचा कि उनके पास कोष की कमी नहीं है, वे सारे साम्राज्य के स्वामी है, फिर भला मोक्ष उन्हें अलभ्य कैसे रहेगा? दूसरे ही दिन वे तीर्थकार के चरणों में उपस्थित हो गये और उनसे बोले, प्रभो मेरा साम्राज्य और सारा कोष आपके चरणों में अर्पित है। कृपया मुझे नरक-गमन से मुक्त कराएं।तीर्थकार के अधरों पर स्मित -रेख खिंच आयी।उन्होंने जान लिया कि महाराजा को अहं ने ग्रसित कर लिया है। जहां गर्व है, वहां मोक्ष कैसा? वे बोले, अपने राज्य के पुण्य नामक श्रावक से सामयिक फल प्राप्त कर लो। यही तुम्हारे उद्धार का उपाय है।

महाराज उस श्रावक के पास पहुंचे और बोले श्रावकश्रेष्ठ मेरी याचना स्वीकार करों, तो जो मूल्य मांगोगे, दूँगा। और उन्होंने सामयिक फल की मांग की। इस पर श्रावक बोला महाराज सामयिक तो समता का नाम है। राग-द्वेष की विषमता को चित्त से दूर कर देना ही तो सामयिक है। इसे कोई कैसे दे सकता है? जब तक आप सम्राट होने का अहंकार छोड़ न दें, वह आपको उपलब्ध नहीं हो सकता।

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

1818 अंग्रेजों तथा मराठों के बीच तीसरा तथा अंतिम युद्ध रामपुर में लड़ा गया।
1846 ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच सोबराऊं की जंग शुरू हुई।
1847 बांग्ला कवि लेखक नवीनचंद्र सेन का जन्म हुआ था।
1921 महात्मा गांधी ने काशी विद्यापीठ का उद्घाटन किया।
1970 मशहूर हिंदी कवि कुमार विश्वास का जन्म हुआ
1990 बृहस्पति की ओर जाते हुए, अंतरिक्ष यान गैलिलियो शुक्र ग्रह के सामने से गुजरा।
1991 मुक्केबाजी की दुनिया के सबसे सफल खिलाड़ी रहे माइक टाइसन को आज ही के दिन बलात्कार का दोषी पाया गया था। अदालत ने उन्हें 6 साल की सजा सुनाई थी।
1996 आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीब ब्लू ने शतरंज में वर्ल्ड चैम्पियन मैरी कास्परोव को पहली बार हराया था।
2009 प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

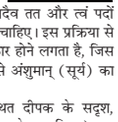

पैङ्गलोपनिषद् (भाग-9)

गतांक से आगे...

यह स्थिति प्राप्त होने पर, प्राक् (पहले) जो, तत्त्वमसि महावाक्य का आशय परोक्ष रूप से विदित होता था, वही अब हस्तामलकवत् अवरोध रहित स्पष्ट विदित होने लगता है और ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है, तब योगी जीवन्मुक्त हो जाता है।

ईश्वर ने पञ्चीकृत भूतों का पुनः अपञ्चीकरण करने की कामना की। अतः उसने ब्रह्माण्ड और उसके अन्तर्गत लोकों को कार्य रूप से पुनः कारण रूप प्राप्त करा दिया। इसके बाद उसने सूक्ष्म अङ्ग, कर्मेन्द्रियों, प्राणों, ज्ञानेन्द्रियों और अन्तःकरण चतुष्टय (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) को एकीकृत करके समस्त भौतिक पदार्थों को उनके कारणभूत पंचक में संयोजित करके भूमि को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महत् (विराट्) में, विराट् को अव्यक्त में और अव्यक्त को पुरुष में क्रमशः विलीन कर दिया। इस प्रकार विराट् हिरण्यगर्भ और ईश्वर भी उपाधियों के विलीन हो जाने पर परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं पञ्चीकृत महाभूतों द्वारा निर्मित और संचित कर्मों से प्राप्त स्थूल देह, कर्मों के क्षय हो जाने तथा सत्कर्मों के परिपाक होने से अपञ्चीकृत हो जाती है। वह देह, सूक्ष्मरूप से एकीभूत होकर, कारण रूप को प्राप्त होकर अन्त में उस कारण के भी कारण कूटस्थ प्रत्यगात्मा में विलीन हो जाती है। फिर विश्व, तैजस और प्राज्ञ की भी अपनी-अपनी उपाधियों के लय हो जाने से ये सभी प्रत्यगात्मा में विलीन हो जाते हैं। अण्ड (ब्रह्माण्ड) अपनी कारण सत्ता के साथ ज्ञानाग्नि में भस्म होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण (ब्रह्म में रत) पुरुष को समाहित चित्त (ब्रह्म में चित्त को समाहित करके) होकर सदैव तत और त्वं पदों के साथ ऐक्य करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया से उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार होने लगता है, जिस प्रकार मेघों के छंट जाने से अंशुमान् (सूर्य) का प्रकाश प्रकट हो जाता है।

कलश के अन्दर स्थित दीपक के सदृश, शरीर में स्थित (हृदय कमल के मध्यस्थित) धूम रहित ज्योति स्वरूप अङ्गुष्ठ परिमाण आत्मा का ध्यान करके जो मुनि अन्तः प्रान्त में स्थित प्रकाशयुक्त कूटस्थ, अव्यय आत्मा का ध्यान नित्य सोते समय तथा मृत्यु के समय भी करता है, वह जीवन्मुक्त है, धन्य है, कृतकृत्य है, ऐसा मानना चाहिए। जीवन्मुक्तत्व (जीवन्मुक्त स्थिति) को छोड़कर वह इस शरीर का परित्याग करके अदेह और मुक्ति को उसी प्रकार प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार पवन स्पन्दन रहित हो जाता है अर्थात् पवन का प्रवाह बन्द हो जाता है। **क्रमशः ...**

भूमकाल दिवस : शहीद गुंडाधुर थे नायक

देश की आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों ने बस्तर में संघर्ष का शंखनाद करने के लिए भूमकाल की शुरुआत की थी। भूमकाल का मतलब है। जमीन से जुड़े लोगों का आंदोलन। इस आंदोलन में बस्तर के हजारों आदिवासियों ने अपने जल, जंगल और जमीन के लिए एक युद्ध लड़ा था। आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत और अपने शोषक वर्ग के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और अपने पारंपरिक हथियारों से उनका सामना किया था।

लड़ाई के दौरान कई आदिवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आदिवासियों ने अपने पारंपरिक हथियारों से अंग्रेजी हुकूमत संघर्ष करते हुए उनकी बंदूकों का सामना किया। बस्तर के लोग हर साल 10 फरवरी को भूमकाल दिवस मनाया जाता है। बस्तर के इतिहासकार

डॉक्टर सतीश जैन बताते हैं कि सन 1910 में बस्तर के आदिवासियों ने अपने जल, जंगल और जमीन को शोषक वर्ग और अंग्रेजों के हाथों में जाता देख और अंग्रेज हुकूमत ती बेड़ियों से तंग आकर भूमकाल की शुरुआत की थी।

भूमकाल का शाब्दिक अर्थ है अपनी भूमि के लिए लड़ाई लड़ना। इस लड़ाई में आदिवासियों की पूरी कौम ने एक होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध की वजह से बस्तर के आदिवासियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था।

भूमकाल के नायक शहीद गुंडाधुर को माना जाता है। धुर्वा समाज के प्रमुख शहीद गुंडाधुर ने बस्तर के आदिवासियों को शोषक वर्ग से निजात दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और इस दौरान वो शहीद हो गए। भूमकाल में ही बस्तर रियासत के तत्कालीन राजा प्रवीण चंद की अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी।

डॉक्टर सतीश बताते हैं कि आज भी बस्तर के आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के लिए लगातार बस्तर में लड़ते आ रहे हैं और वर्तमान में भी अपने इष्ट देवता को बचाने के लिए बैलाडीला में अपने पारंपरिक हथियारों को लेकर पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए है। डॉक्टर सतीश का कहना है कि पहले के भूमकाल और वर्तमान के भूमकाल में काफी अंतर आ चुका है।

धार्मिक आस्था का केन्द्र राजिम

प्रो. अश्विनी केशरवानी

महानदी, सोढुल और पैरी नदी के संगम के पूर्व दिशा में बसा राजिम प्राचीन काल से छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्र रहा है। दक्षिण कोशल में विख्यात् राजनीतिक तथा सांस्कृतिक धारा से सदैव सामंजस्य बनाये रखने वाला यह ऐतिहासिक नगरी रही है। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व राजिम को प्राप्त है वह स्थान किसी दूसरे स्थान को नहीं है। रतनपुर के कलचुरी नरेश जाजल्लदेव प्रथम एवं रत्नदेव द्वितीय के विजय का उल्लेख उसके सामंत जगपालदेव के राजीव लोचन मंदिर से प्राप्त अन्य शिलालेखों में हुआ है जिसके संबंध में अन्य अभिलेखों में कोई जानकारी नहीं मिलती।

राजिम नाम को सार्थकता के लिये जनश्रुतियों का सहारा लिया जा सकता है। जनश्रुति से पता चलता है कि राजिम नामक एक तेलिन के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि एक समय जब राजिम तेल बेचने जा रही थी तो वह रास्ते में पड़े एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी जिससे टोकरी में रखा तेल गिर गया। तेल के गिर जाने से वह अपने सास-ससुर से मिलने वाली प्रताड़ना की कल्पना मात्र से भयभीत होकर विलाप करने लगी और ईश्वर से उनसे रक्षा करने की प्रार्थना करने लगी। कुछ देर रोने के बाद अपने को संयत करके घर लौटने के लिये जब वह टोकरी को उठाने लगी तब तेल पात्र को भरा पाकर चकित हो गयी। फिर वह खुशी खुशी पास के गांव में तेल बेचने गयी वहां सुबह से शाम तक तेल बेचती रही लेकिन तेल पात्र खाली नहीं हुआ। इससे इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ।

प्रतिदिन की तुलना मे अधिक पैसा कमाने के बावजूद तेल पात्र को तेल से भरा पाकर खुशी से वह घर लौटी। बाद में राजिम को एक रात स्वप्नादेश हुआ कि उस स्थान में दबे देव प्रतिमा को निकालकर प्रतिष्ठित करो। निर्दिष्ट स्थान की खुदाई करने पर एक श्यामवर्ण विष्णु भगवान की चतुर्भुजी प्रतिमा मिली। तब राजिम उस मूर्ति को सशर्त कि भगवान के नाम के साथ उसका भी नाम जोड़ा जाये, देने को राजी हो गयी। इस प्रकार मंदिर का नाम ''राजिम-लोचन'' हुआ जो आग्र चलकर ''राजीव लोचन'' कहलाने लगा।

रायपुर जिला गजेटियर के अनुसार सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद रायबहादुर हीरालाल ने जुते बैल युक्त कोल्हू को राजिम तेलिन की वंश परम्परा से चले आने वाले व्यवसाय की पतीकात्मक अभिव्यक्ति बताया है यह शिलापट्ट सती स्तम्भ कहलाता है। इसे आधार मानकर उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि यदि राजिम तेलिन से संबंधित जनश्रुति के मूल में सत्यांश है तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वह अपने अपराध देव राजीव लोचन के सामने सती हुई थी।

राजिम नाम के संबंध में एक दूसरी जनश्रुति भी प्रचलित है। इसका उल्लेख सर रिचर्ड जेकिंस ने एशियाटिक रिसर्चेज में किया है। उसके अनुसार राजिम श्रीराम के समकालीन राजीवनयन नाम किसी राजा की राजधानी थी। राजा राजीव नयन ने श्रीराम के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को पकड़कर महानदी के तट पर निवास कर रहे कंदर्मक ऋषि को सौंप दिया। घोड़े की रक्षा कर रहे शत्रुघ्न जब ऋषि कंदर्मक से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा को मांगा लेकिन ऋषि के मना करने पर शत्रुघ्न के आक्रमण कर दिया और ऋषि के क्रोधाग्नि से सेना सहित शत्रुघ्न मारे गये। अश्वमेघ यज्ञ की सफलता के लिये स्वयं श्रीराम को यहां आना पड़ा था। यहां श्रीराम के आने पर राजा राजीव नयन बिना युद्ध किये उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। ऋषि कंदर्मक भी श्रीराम की विनती करने पर शत्रुघ्न सहित सेना को जीवित कर दिये। तब श्रीराम यहां अपना अस्तित्व ''राजीव लोचन'' के रूप में छोड़ते गये। आज भी यहां श्रीराम की मूर्ति प्रतिष्ठित है।

कलचुरी कालीन राजिमः- राजीव लोचन मंदिर के महामंडप को पार्श्व भित्ति पर कलचुरि संवत् 896 का एक शिलालेख है जिसे रतनपुर के कलचुरी नरेशों के सामंत जगपालदेव ने उत्कीर्ण कराया था। इस अभिलेख में जगपालदेव के वंश का नाम ''राजमाल'' उल्लेखित है। कनिंघम ने राजमाल वंश नाम से ही ''राजम-राजिम'' नाम की उत्पत्ति मानी है। यद्यपि राजमाल से राजिम नामकरण का प्रचलन संभव प्रतीत होता है परन्तु शब्द साम्य के आधार पर इस अनुमान को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। अधिकांश विद्वान ''राजिम'' को ''राजीव'' का विकृत रूप मानते है। इस संदर्भ में वे ''राजीव लोचन'' से भगवान विष्णु के एक विरुद का आश्रय स्वीकार करते हैं इसकी प्रमाणिकता के लिये वहां की प्रसिद्ध विष्णु की प्रतिमा को प्रस्तुत किया जा सकता है।

गुप्त कालीन मूर्तिकला का केन्द्रः- राजीव लोचन मंदिर पंचायत शैली का है मुख्य मंदिर ऊँचे विस्तृत चबुतरे पर बनाया गया है। उसके चारों ओर चार देवलिकाएं अर्थात छोटे मंदिर बनाए गये है। मुख्य मंदिर के तीन भाग है मंडप और दक्षिण-पश्चिम छोर से सीढ़ियां बनी है जिसमें चढ़कर मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है मंडप के बीचोबिच स्तम्भों की दो पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में छः स्तम्भ के नीचे का भाग सपाट है जबकि उपरी भाग में गंगा-यमुना, वराह, नृसिंग,सूर्य और दुर्गा की देव प्रतिमाएं अंकित हैं गर्भगृह में भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा है वे अपने चारों हाथ में शंख, चक्र,,पद्म और गदा धारण किये हुये है। डॉ. विष्णु सिंह ठाकुर राजिम के मंदिरों के शिल्प के संबंध में लिखते हैं - ''प्राचीन कलाकृतियां जहां एक ओर भौतिक जीवन के हर्ष-विषाद के क्षणों को सुख-दुख की अनुभूतियों को शील, संयम आदि भौतिक गुणों तथा समृद्धि एवं ऐश्वर्य को प्रस्तुत करती है, वही दूसरी ओर उनके प्रति कलात्मकता में अध्यात्म का स्वर सद्यः मुखरित रहता है। यह दूसरा पक्ष ही भारतीय कला का प्राण बिन्दु रहा है।''

''राजिम माहात्म्य'' में इसे ''पद्म क्षेत्र'' कहा गया है। इसमे आंचलिक विश्वास एवं धार्मिक का पुट है। सृष्टि के आरंभ में भागवान विष्णु के नाभि कमल की एक पंखुड़ी पृथ्वी पर गिरी पड़ी।चारों दिशाओं में स्थित धाम और गुप्त तीर्थधाम शिवरीनारायण के बाद राजिम का दर्शन साधी गोपाल के रूप में किया जाता है माघ पूर्णिमा को यहां मेला लगता है।

गांधी आज

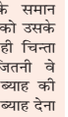

विधवा विवाह

हिन्दू विधवा त्याग और पवित्रता की मूर्ति है। यह माता की मात सबके लिए पूज्य है। उसे अशुभ समझनेवाला हिन्दू समाज महान करता है। शुभ कार्यों में उसकी उपस्थिति और आशीर्वाद पाने का प्रयत्न करना पवित्र विधवा को समाज का भूषण समझकर उसके मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए।

किन्तु स्त्री जाति के प्रति पोषित प्रचारित तुच्छ भाव ने के साथ अन्याय करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। इससे हिन्दू विधवा की स्थिति अछूतों के समान ही दयाजनक हो गई है।

विधवा त्याग की मूर्ति है, पर इस कारण वैधव्य जबरदस्ती कराने की चीज नहीं है। बलात्कार से कराया हुआ त्याग उसमें रहने वाली दिव्यता का नाश करता है और उसे पूजनीय तथा आदर्श बनाने के बदले दया का पात्र बना डालता है। इस कारण विधुर हुए पुरुष को पुनर्विवाह करने का जितना अधिकार माना गया है उतना ही विधवा को भी है।

बालविधवा बालविवाह का परिणाम है। 15-16 की उम्र से पहले कन्या का विवाह होना ही न चाहिए। ऐसे विवाह के फलस्वरूप प्राप्त वैधव्य तो वैधव्य ही नहीं है। ऐसी विधवा को कुँवारी कन्या के समान मानकर माँ-बाप को उसके ब्याह की उतनी ही चिन्ता करनी चाहिए जितनी वे कुँवारी बेटी के ब्याह की करते हैं और उसे ब्याह देना चाहिए।

विवाहेच्छु हिन्दू युवकों से ऐसी बालविधावाओं से ही व्याह करने का आग्रह रखने की सिफारिश करना उचित होगा। यदि युवक विधुर फिर से विवाह करना चाहे तो उसे विधवा से ही विवाह करना धर्म समझना चाहिए।

`धर्मांतरण के विरोध में सर्व समाज का धरना

दंतेवाड़ा। बीते माह नारायणपुर में हुई घटना के बाद धर्मांतरण का विरोध करने वालों पर पुलिस द्वारा रासुका लगाकर जेल भेजने तथा बस्तर अंचल में बढ़ते अवैध धर्मांतरण के विरोध में बुधवार को एक दिवसीय सर्व हिन्दू समाज के बैनर तले प्रांत व्यापी सत्याग्रह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रदेश भर में किया गया। इसी कड़ी में दंतेवाड़ा जिले में भी धर्मातरण के विरुद्ध सर्व समाज ने धरना दिया और अवैध तरीके से धर्मांतरण करवाने वालों को सख्त चेतावनी देते कहा कि सुधर जाओ नहीं तो हिन्दू समाज ऐसे अधर्मियों को किस तरह से सुधारना है जानता है।

धरना प्रदर्शन के दौरान धरना स्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपत्र हुआ समापन उपरांत प्रशासन को ज्ञापन सौंप नारायणपुर घटना के लिए जिन निर्दोष लोगों पर रासुका लगाकर उन्हें जेल भेजा गया है उनकी जल्द से जल्द रिहाई मांग की गई ।गौरतलब है कि बस्तर अंचल में जिस तरह से एकाएक कुछ वर्षों में धर्मातरण तेजी से बढ़ा है इसकी चिंता अब हिन्दू समाज के सभी वर्गों के लोगों को सताने लगी है। बढ़ते धर्मांतरण मुद्दे को लेकर बुधवार 8 फरवरी को दंतेवाड़ा

जिला मुख्यालय के आंवराभाटा दुर्गा मंडप स्थल पर सर्व समाज द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया ।

जिसमें साहू समाज, यादव समाज, कोया समाज, धाकड़ समाज, हल्वा समाज, गुप्ता समाज, कुर्मी समाज, देवांगन समाज, कलार समाज, सोनार समाज समेत कई अन्य समाज का समर्थन मिला ।उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए अंचल का प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता एवं शंखनी डंकनी महिला उत्थान समिति की प्रमुख सुश्री बुध ताती ने धर्मातरण पर गहरी चिंता जताते कहा कि ईसाई धर्म का मुख्य निशाना हमारे बस्तर के भोले भाले, शांतिप्रिय आदिवासी हैं जिन्हें बहला फुसलाकर, प्रलोभन देकर, अच्छे जीवन जीने का झूठा सपना दिखाकर उनका धर्मातरण करवाया जा रहा है। आदिवासियों की संस्कृति, संस्कार को बर्बाद करने का भरपुर प्रयास मिशनरियों द्वारा किया जा रहा है जिसे हमें सर्व समाज को मिलकर रोकना होगा ।

धर्मातरण एक बहुत ही बड़ा मुद्दा इस समय हमारे सामने है इन चुनौतियों से हमें लडना ही होगा। यादव समाज के पदाधिकारी गणेश यादव ने भी धर्मातरण पर कटाक्ष करते कहा कि आज गांवों से होते हुए धर्मातरण शहर तक आ पहुंचा है। वार्ड मोहल्लों में भी अवैध रूप से चर्च, प्रार्थना सभा खोलकर लोगों को प्रलोभन एवं सब्जबाग दिखाकर धर्मातरण का खेल मिशनरी के लोग खेल रहे हैं। हम हिन्दू समाज को सतर्क एवं सजग रहने की आवश्यकता है धाकड़ समाज के प्रमुख बिरबल ठाकुर ने कहा कि कहीं ना कहीं हमारा समाज खुद ही हमारे लोगों की चिंता करना छोड़ दिया है। जिसका फायदा मिशनरी के लोग उठा रहे हैं। हमें समाज के हर तबकों का सहारा बनना पड़ेगा जागरूकता भी एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है ।धर्मातरण को रोकने के लिए अन्य समाज प्रमुखों ने भी पुरजोर तरीके से अपने अपने विचार धरना प्रदर्शन के दौरान रखा और एक स्वर में धर्मातरण बंद करने तथा ईसाई मिशनरियों को बस्तर छोड़ने की चेतावनी दी। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में सर्व समाज के सैकड़ों महिला, पुरूष, युवा शामिल रहे। धरना उपरांत जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप नारायणपुर घटना में शामिल निर्दोष लोगों पर से रासुका हटाने तथा धर्मातरण करवाने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की मांग दोहराई गई।

राज्य महिला आयोग ने महिला उत्पीड़न प्रकरणों पर जनसुनवाई की

रायपुर। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य डॉ अनीता रावटे, श्रीमती नीता विश्वकर्मा ने आज राज्य महिला आयोग कार्यालय शास्त्री चौक रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जनसुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ नायक ने अपने कार्यकाल की आज 158 वीं जनसुनवाई की। रायपुर की आज 84 वीं जनसुनवाई में कुल 35 प्रकरण रखे गये थे। इनमे से 4 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गए, शेष प्रकरण को आगामी सुनवाई में की जाएगी। आज के एक प्रकरण में आवेदिका अपनी दृष्टिहीन बहन और गांव की सरपंच को लेकर सुनवाई में उपस्थित हुई। आवेदिका की बहन ने बताया कि उसका इंदिरा आवास उसके सौतेले बेटे बहु ने छीन लिए हैं और उन्हें घर से निकाल दिए हैं। जिसकी शिकायत आवेदिका ने किया है। आयोग द्वारा अनावेदकगण को समझाइश दिया गया है कि इंदिरा आवास में आवेदिका के बहन के

नाम पर होने की स्थिति पर उन्हें इंदिरा आवास को तत्काल देना होगा। आवेदिका की बहन की उम्र लगभग 75 वर्ष है ।गांव की सरपंच ने बताया कि ग्राम पंचायत के इंदिरा आवास के अभिलेख देखने से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आयोग की काउंसलर को गांव में जाकर मौके पर समस्त दस्तावेज और बयान लेने के निर्देश देने के साथ ही आयोग में रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा गया ।इसके पश्चात प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। एक अन्य प्रकरण में पिछली सुनवाई में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बलौदाबाजार अधिकारी को 4 माह का समय दिया गया था ।आज की सुनवाई में अनावेदिका ने जो दस्तावेज दिखाए है उसके माह फरवरी के पत्र के अलावा कोई पत्राचार नही दिखा है ।स्पष्टीकरण पूछने पर अनावेदिका ने बताया कि मौखिक रूप से रिमाइंडर किया था। किंतु अब तक जवाब नही आया है आयोग द्वारा पुनः पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वर्ष 2013-14 में आवेदिका के पति का लगभग 28 से 29 हजार रुपये का बकाया वेतन की स्वीकृति के लिए पत्र आ गया है पर शेष 62 हजार 9 सौ 48 रुपये का वर्ष 2017 के माह मार्च से माह नवम्बर के वेतन का डिटेल जिस अधिकारी के पास है वे स्थानान्तरण हो गए हैं ।वे विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर में पदस्थ है और उनके द्वारा अब तक किसी भी प्रकार से जवाब नहीं दिया गया है। अनावेदिका के द्वारा उनका डिटेल दिया गया है। आगामी सुनवाई में विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर में पदस्थ अधिकारी को समस्त दस्तावेज सहित उपस्थित होने हेतु आयोग से पत्र प्रेषित किया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

सहकारी समिति का निर्वाचन कार्यक्रम जारी

बिलासपुर। छ.ग. राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार सी.पी. बाजपेयी को छ.ग. उच्च न्यायालय अधिकारी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति बिलासपुर का रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नियोजन पत्र की प्राप्ति 15 फरवरी, नियोजन पत्र की जांच 16 फरवरी, आमसभा, मतदान, मतगणना 25 फरवरी और 28 फरवरी को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की बैठक सूचना जारी कर 04 मार्च को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों का निर्वाचन सम्पन्न कराया जायेगा।

विधानसभा को समय पर जवाब भेजने नोडल अधिकारी नियुक्त

बिलासपुर। विधानसभा सत्र के दौरान सवालों का समय पर जवाब भेजने के लिए अपर कलेक्टर श्री राम अधारी कुरूवंशी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री कुरूवंशी का मोबाईल नंबर 94242-82735 एवं लैण्ड लाइन नंबर 07752-224030 हैं। जिला कार्यालय द्वारा जारी एक अन्य आदेश में इस दौरान अधिकारी-कर्मचारी को मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए गए हैं। सक्षम अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना वे मुख्यालय से बाहर नहीं जा पाएंगे। मालूम हो कि 1 मार्च से 24 मार्च तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आहूत किया गया है।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कुश्ती स्पर्धा में छग के मनु यादव ने जीता गोल्ड

रायपुर। मध्यप्रदेश में चल रहे पांचवीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स कुश्ती स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। छत्तीसगढ़ के पहलवान मनु यादव ने 51 किग्रा भार वर्ग ग्रीको रोमन स्टेल कुश्ती में खेलते हुए 1 राउंड में हरियाणा के पहलवान अमरजीत को 8-0 के पॉइंट से तकनीकि दक्षता से हराया। दो राउंड में एमपी के पहलवान को हराया और सेमी फाइनल में एशियाई गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड कैडिट सिल्वर मेडलिस्ट हरियाणा के रोनित शर्मा को 4-2 के प्वाइंट से हराया। फाइनल मैच में महाराष्ट्र के पहलवान को मात्र 30 सेकेंड में तकनीकी दक्षता के आधार पर हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया और छत्तीसगढ़ को गौरान्वित किया।

छत्तीसगढ़ चेम्बर में विधिक सलाहकार समिति का गठन

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि चेम्बर, व्यापारिक संगठन एवं व्यापारीगण के हितों के लिये, विधिक सलाहकार समिति का गठन किया गया है जो कि समय पर व्यापार एवं उद्योग के अधिनियमों से संबंधित शंकाओं का समाधान करेंगे एवं सुझाव देंगे। विधिक सलाहकार समिति (लीगल एवं टेक्नीकल टीम) में निम्न सलाहकार शामिल हैं जिनमें आयकर - सी.ए. आर.बी. दोशी, सी.ए. साक्षी अग्रवाल, सी.ए. किशोर बरडिया, वित्त एवं सब्सिडी - सी.ए. अंकुश गोलछा, सी.ए. रवि ग्वालानी (सह समन्वयक), जीएसटी - सी.ए. मुकेश मोटवानी (सह समन्वयक), सी.ए. जितेंद्र खनूजा, आरओसी एवं जीएसटी - सी.एस. सतीश तवानिया, सी.एस. बृजेश अग्रवाल, वेट एवं जीएसटी- अधिवक्ता दयाल राजपाल, अधिवक्ता सुनील अग्रवाल, रायगढ़, उपभोक्ता -अधिवक्ता राजेश भावनानी, भविष्य निधि (पीएफ)/कर्मचारी राज्य बीमा योजना (इएसआईसी)-खुशीकांत सोलंकी, विधिक - अधिवक्ता आनंद मोहन ठाकुर, अधिवक्ता रामू व्यास शामिल है।

देश की प्रथम मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को

बिलासपुर। छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशन तथा जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर श्री अशोक कुमार साहू के मार्गदर्शन में देश की प्रथम मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन ''स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवाओं'' के तहत् बिलासपुर की मिनी माता बस्ती जरहाभाठा में दिनांक-11.02.2023 को सुबह 10.30 बजे किया जायेगा। उक्त मोहल्ला लोक अदालत हेतु मोबाइल वैन (वाहन) को छग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यपालक अध्यक्ष छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी द्वारा हरी झंडी दिखाकर सुबह-10.00 बजे जिला न्यायालय परिसर बिलासपुर से रवाना किया जायेगा। उक्त मोहल्ला लोक अदालत में सफाई एवं स्वच्छता प्रणाली की सेवा से संबंधित प्रकरणों का निराकरण मौके पर उपस्थित स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पंकज कुमार जैन एवं सदस्य श्री सुरेश सिंह गौतम एवं सदस्य श्रीमती शालिनी मिरी के माध्यम से किया जायेगा। उक्त मोहल्ला लोक अदालत में नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक-11/02/2023 को किया जावेगा। जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर श्री अशोक कुमार साहू के निर्देशन में नेशनल लोक अदालत में मामलों के निराकरण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा जिला बिलासपुर एवं गौरेला पेण्ड्रा मरवाही हेतु न्यायिक अधिकारियों के कुल 32 खण्डपीठ तथा राजस्व न्यायालयों के कुल 45 खण्डपीठों का गठन किया गया है।

पुलिस का दावा कई नक्सली मुठभेड़ में मारे गए

बीजापुर। जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र अंतर्गत सुकमा जिले के सरहदी इलाके में गुंडम और छुटवाई के जंगलों में बुधवार को हुई नक्सली मुठभेड़ में एक ग्रामीण पुनेम लखमू निवासी ग्राम गुंडेम की मौत हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने लखमू को मारा है। वहीं बीजापुर के एएसपी चंद्रकांत गवर्णा का कहना है कि घटना स्थल पर खून के धब्बे मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मुठभेड़ में कई नक्सली मारे गए हैं, जिनका शव नक्सली अपने साथ ले जाने में कामयाब रहे, मौके से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद किया गया है। उन्होने ग्रामीण की मौत की जानकारी नही होने की बात कही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गुंडम और छुटवाई के जंगलों में बुधवार को हुई नक्सली मुठभेड़ के संबध में बीजापुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि, बीजापुर-सुकमा जिले के सरहदी इलाके गुंडम और छुटवाई के जंगलों में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। मुखबिर की सूचना पर

डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम को मौके के लिए रवाना किया गया था। जैसे ही जवान जंगलों में पहुंचे वहां घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों की जवाबी कार्यवाही में नक्सलियों को नुकसान हुआ है। मौके से बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद किया गया है। एएसपी चंद्रकांत गवर्णा ने कहा कि मुठभेड़ में ग्रामीण की मौत होने की जानकारी उन्हें नहीं है।

10 किलो टिफिन बम बरामद

दंतेवाड़ा। 231 बटालियन सीआरपीएफ ने नक्सलियों के घातक हथियार को एकबार फिर नाकाम किया है। गुरुवार सुबह एरिया क्लीयरेंस में निकली सुरक्षा बल के जवानों ने दस किलो का टिफिन बम बरामद किया।

गुरुवार को सुबह लगभग 9 बजे 231 वीं वाहिनी अपने परिचालनिक क्षेत्र में सुरेन्द्र सिंह कमाण्डेंट 231 बटालियन के निगरानी में आर एस ओ ड्यूटी बी/231 बटालियन एके देशबन्धु व एफ/231 बटालियन मुकेश कुमार चौधरी, उप कमाण्डेंट के नेतृत्व में निकली हुई थी। सुरक्षाबलों की टुकड़ी सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए सावधानी बरतते हुए कोण्ड़ासांवली से कमारगुड़ा कैम्प की ओर एरिया क्लीयरेंस करते हुए जा रहे थे, तभी वाहिनी के बम्ब निरोधक दस्ता टीम को डीएसएमडी के माध्यम से आईईडी लगे होने का संकेत मिला।

एके देशबन्धु, सहायक कमाण्डेंट द्वारा ड्यूटी पार्टी को सर्तक किया व संदिग्ध ईलाके की बारीकी से छान-बीन करने पर 1 जिंदा आईईडी टिफिन बम्ब प्रेशर मेकानिज्म वजन लगभग 10 किलोग्राम बरामद किया गया।

राजीव युवा मितान क्लब की नियमावली में संशोधन पर हुआ विचार-विमर्श

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में राजीव युवा मितान क्लब योजना की कार्यकारिणी केन्द्रीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजीव युवा मितान क्लब की नियमावली में संशोधन पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्रीमती रेणुजी पिल्ले भी शामिल हुई।

बैठक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों ने राजीव युवा मितान क्लब की नियमावली के वर्तमान प्रावधानों की जानकारी प्रस्तुत की। इसी प्रकार से क्लब के वित्तीय नियमों के पालन एवं सुसंगत पंजियों का संधारण सुनिश्चित करने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया। इसी प्रकार से क्लब में शिक्षा, खेल, समाज सेवा, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण में उच्च योग्यता रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता देने का प्रस्तावित प्रावधान के बारे में सदस्यों ने अपने विचार रखें।

बैठक में राजीव युवा मितान क्लब योजना हेतु खेल एवं युवा

कल्याण विभाग के बजट में स्वीकृत राशि में से एक निश्चित राशि प्रशासकीय व्यय हेतु रखने और शेष राशि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित शासी निकाय के निर्देश पर संचालक खेल एवं युवा कल्याण के द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को राजीव युवा मितान क्लब की जिला स्तरीय समिति के बैंक खाते में अंतरित करने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया। इसी तरह से राजीव युवा मितान क्लब द्वारा अनुदान राशि का व्यय करने वित्तीय नियमों का पालन कर राशि का आहरण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक की तत्काल भुगतान आवश्यक ना हो। बैठक में अन्य प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव एन.एन. एक्का,सहित समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए।

मीडिया को कानून के साथ नैतिक संयम की जरुरत-प्रो. बल्देवभाई शर्मा

रायपुर। अग्रसेन महाविद्यालय में पत्रकारिता विभाग द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सहयोग से आज से तीन दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारम्भ हुआ. इस अवसर उद्घाटन सत्र में कुशाभाऊ ठाकरे विश्व विद्यालय के कुलपति प्रो बल्देवभाई शर्मा ने कहा कि मीडिया को कानून के अनुपालन के साथ ही नैतिक आत्मसंयम भी जरुरी है. कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित नेहरु ग्राम बालभारती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ राममोहन पाठक ने कहा कि आजादी से पहले हमारा मीडिया बहुत नैतिक था. हमें वहीँ से आगे का रास्ता तलाशना होगा. इस अवसर पर स्वागत भाषण करते हुए महाविद्यालय के डायरेक्टर डॉ. वी.के. अग्रवाल ने कहा कि अपने प्रयोग में मीडिया अराजक न हो जाए, इसलिए मीडिया के लिए कानून का दायरा बनाना आवश्यक है. वहीँ

आभार प्रदर्शन करते हुए प्राचार्य डॉ युलेन्द्र कुमार राजपूत ने कहा कि मीडिया का दायित्व समाज को जागरूक करने का है. यदि इसमें कुछ बदलाव होता है, तो मीडिया को भी कानून का संयम मानना जरुरी हो जाता है. उन्होंने सभी वक्ताओं को उनके प्रेरक विचारों के लिए साधुवाद दिया. महाविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटर प्रो. अमित अग्रवाल ने कहा कि इस राष्ट्रीय सेमीनार से महाविद्यालय का दायरा बढ़ा है, और इसके बाद आगे भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे. उद्घाटन सत्र के बाद पहले तकनीकी सत्र में छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक अकादमी के सहायक प्राध्यापक डॉ सुरेशमणि त्रिपाठी ने सूचना का अधिकार एवं मीडिया की भूमिका- विषय पर अपनी पर प्रस्तुति में विभिन्न स्लाईड के जरिये कहा कि लोकतंत्र में जनता को शासन और प्रशासन के कामकाज के बारे में जानने का अधिकार निश्चित रूप से है. चूँकि जनता के टैक्स के पैसे से सभी को वेतन मिलता है, तो जनता के प्रति सभी की जवाबदेही होनी ही चाहिए. इसी भावना से सूचना का अधिकार लागू किया गया. लेकिन इसका दुरूपयोग नहीं होना चाहिए. इसीलिए इसमें कुछ धाराओं के तहत ऐसे प्रावधान किये गए हैं कि हर तरह की जानकारी जनता को नहीं दी जा सकती।

गांव-गांव में जले बजट के पुतले, किसान सभा ने कहा - बजट कॉरपोरेटों का, अंगूठा मोदी का

कोरबा। अखिल भारतीय किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के देशव्यापी आह्वान पर कोरबा में छत्तीसगढ़ किसान सभा ने जन विरोधी केंद्रीय बजट के खिलाफ गंगानगर, मड़वाढोढा, पुरैना समेत कई गांवों में प्रदर्शन और पुतला दहन करते हुए 'काला दिवस' मनाया।

छत्तीसगढ़ किसान सभा के जिला अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर और जिला सचिव प्रशांत झा विरोध प्रदर्शनों के इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह बजट कॉरपोरेटों ने, कॉरपोरेटों द्वारा, कॉरपोरेटों के लिए बनाया है, जिस पर मोदी सरकार ने केवल अंगूठा लगाया है। इसीलिए इस बजट में न तो आम जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाने का उपाय है, न सामाजिक क्षेत्र में निवेश

बढ़ाकर रोजगार सृजन की चिंता। उल्टे मनरेगा, खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, बीमा, सिंचाई, कृषि, श्रम और अन्य सभी सामाजिक क्षेत्रों में पिछले वर्ष के बजट की तुलना में इस वर्ष भारी कटौती की गई है और कॉरपोरेटों को टैक्स में छूट ही दी गई है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन दुकानों से मिलने वाले 5 किलो सस्ते अनाज से भी वंचित कर दिया गया है। इससे देश की जनता और बदहाल होगी।

किसान सभा नेताओं मोदी सरकार पर देश के किसान आंदोलन से सरकार ने विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्वामीनाथन आयोग के आधार पर फसल का लाभकारी मूल्य देने के वादे पर अब सरकार ने चुप्पी ही साध ली है, जबकि पिछले पांच सालों में किसानों की आय दुगुनी होने के बजाय और गिर गई है। इन नवउदारवादी नीतियों के कारण देश कॉर्पोरेट इंडिया और तड़पते भारत में विभाजित हो गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 160 एमवीए का नया ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत

पहले इस सब-स्टेशन की क्षमता 160 एमवीए थी, जो अब बढ़कर 320 एमवीए हो गई

रायपुर। प्रदेश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लगातार पारेषण प्रणाली में वृद्धि कर रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हो, इसके लिए क्षमता विस्तार का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा के छुरी स्थित 220/132 केवी एक्ट्रा हाई वोल्ट उपकेंद्र (ईएचवी सब-स्टेशन) में 160 एमवीए (मेगावोल्ट एंपीयर) का ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया। 9.27 करोड़ की लागत से निर्मित इस ट्रांसफार्मर को ट्रांसमिशन कंपनी की प्रबंध निदेशक श्रीमती उज्जवला बघेल ने पूजा-अर्चना कर ऊर्जीकृत किया।

ट्रांसमिशन कंपनी प्रदेश में पारेषण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इसके लिए पूंजी निवेश योजना के तहत सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। कोरबा के छुरी स्थित 220/132 केवी ईएचवी सब-स्टेशन में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई गई है। पहले इस सब-स्टेशन की क्षमता 160 एमवीए थी, जो अब बढ़कर 320 एमवीए हो गई है। इससे कोरबा क्षेत्र के 134 से अधिक गांवों मे गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हो

सकेगी। साथ ही छह जिलों में विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा।

इसके अलावा एसईसीएल के गेवरा, कुसमुंडा और विश्रामपुर ,सरगुजा क्षेत्र में भी निर्बाध विद्युत आपूर्ति में मदद मिलेगी। ट्रांसमिशन कंपनी की प्रबंध निदेशक श्रीमती बघेल ने सफलतापूर्वक ऊर्जीकरण के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। छुरी में 220/132 केव्ही ईएचटी सबस्टेशन पहले से ही संचालित है, परन्तु विद्युत की मांग में वृद्धि के कारण ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई। तदानुसार पॉवर कंपनी ने इस सबस्टेशन में 160 एमवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित किया। इससे इस क्षेत्र के बढ़ती हुई विद्युत मांग की आपूर्ति सुगमता से की जा सकेगी। साथ ही आपात परिस्थिति में एक ट्रांसफार्मर फेल होने पर भी विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रह सकेगी। लोड बढ़ने पर दोनों ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति होगी, जिससे लो-वोल्टेज की समस्या नहीं रहेगी।

इस अवसर पर मुख्य अभियंता (सी एंड एलएम)श्री केके भगत, मुख्य अभियंता (सिविल) श्री केएस रामाकृष्णा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री अविनाश सोनेकर, अधीक्षण अभियंता सर्वश्री सीएम बाजपेयी, डीएस पटेल, श्री सिदार, कार्यपालन अभियंता श्री आईके साय, नवीन केरकेट्टा, बीबी नेताम, अजय कंवर, एससी भगत, सहायक अभियंता सर्वश्री तामेश्वर सिंह, प्रदीप इंदवीर, तपनकांत नेताम, विजय पात्रे सहित भेल से श्री सुनील पाटिल एवं श्रीमती अदिति श्रीवास्तव सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

संक्षिप्त ख़बरें

एन.पी.एस.-ओ.पी.एस. वयन के विकल्प के लिए हुई कार्यशाला

रायपुर। नवीन पेंशन योजना (एन.पी.एस.) अथवा पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.) के चयन हेतु अटल नगर नवा रायपुर स्थित इन्द्रावती भवन के ऑडिटोरियम हाल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला एन.पी.एस. और ओ.पी.एस. को लेकर अधिकारियों-कर्मचारियों मन में उठे शंका का समाधान किया गया। कार्यशाला में वित्त नियंत्रक श्री टी.आर. सोरी, अपर संचालक श्री के.एल. रवि और श्री आर.पी. एस. चौहान सहित विभिन्न विभागों के 400 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। गौरतबल है कि राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए एन.पी.एस. अथवा ओ.पी.एस. में रहने हेतु विकल्प प्रस्तुत किया गया है। कार्यशाला के माध्यम से कर्मचारियों के विकल्प चयन में होने वाली असुविधा एवं शंकाओं का निराकरण किया गया। कार्यशाला में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्री आलोक राय ने बताया कि 1 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच नियुक्त शासकीय सेवकों को एन. पी. एस. अथवा ओ. पी. एस में रहने हेतु विकल्प का चयन किया जाना अनिवार्य है। विकल्प चयन के लिए 24 फरवरी 2023 निर्धारित है।

कृषि विश्वविद्यालय के स्वयं सेवक एवं कार्यक्रम अधिकारी को सम्मान

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वंय सेवक पी.एच.डी. छात्र हरेन्द्र कुमार एवं कृषि महाविद्यालय, नारायणपुर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की कार्यक्रम अधिकारी डॉ. रत्ना नशीने को विगत दिनों दुर्ग जिले में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में हरेन्द्र कुमार को सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक सम्मान एवं 10 हजार रूपये नगद राशि एवं डॉ. रत्ना नशीने को श्रेष्ठ कार्यक्रम अधिकारी सम्मान एवं 11 हजार रूपये नगद राशि से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सम्मानित स्वयं सेवक एवं कार्यक्रम अधिकारी ने विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल से सौजन्य भेट करके इस उपलब्धि के बारे में अवगत कराया। कुलपति डॉ. चंदेल ने उन्हें एवं उनसे जुड़े पूरी टीम को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉ. संजय शर्मा, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डॉ. जी.के.दास, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रायपुर, डॉ पी .के. सांगोडे कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर उपस्थित थे।

केंद्र से दी जा रही राशि पर वाहवाही लूटना बंद करें भूपेश- साव

कांग्रेस विधानसभा में स्वीकार कर चुकी है कि धान खरीदी राज्य एजेंसी के रूप में करता हैः भाजपा

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ,सांसद अरुण साव ने कहा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान को लेकर राज्य सरकार ने आंकड़े जारी करने की चुनौती स्वीकार नहीं की। क्योंकि राज्य सरकार ने भ्रामक जानकारी दी थी। कांग्रेस जनता को सत्य बताने की हिम्मत नहीं जुटा सकी तो उन्होंने राष्ट्रीय परिषेक्ष की जगह राज्य के आंकड़े जारी किए हैं।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने फिर एक चुनौती दी है कि कांग्रेस में दम है तो बताए कि धान का कितना पैसा उन्होंने किसानों को दिया और उसी धान से बना चावल खरीदकर केंद्र ने कितना पैसा दिया? उन्होंने कहा कि आंकड़े जारी किए तो मालूम हो जायेगा की धान खरीदी के सोलह आने में से मात्र 1आना राज्य सरकार दे रही है। केंद्र सरकार धान खरीदी के लिए बारदाने से लेकर परिवहन तक सभी व्यय वहन करती है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भूपेश बघेल केंद्र का चंदन घिसकर खुद को सुगंधीलाल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस केंद्र सरकार के पैसों से वाहवाही लूटना बंद करे और आंकड़े जारी करे कि छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र सरकार कितना पैसा दे रही है और कांग्रेस की भूपेश सरकार कितना पैसा दे रही है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों का 61 लाख मैट्रिक टन चावल जो लगभग 90 से 95 लाख मैट्रिक टन धान होता है। उसे केंद्र की मोदी सरकार खरीद रही है। कांग्रेस आंकड़े जारी करने की चुनौती स्वीकार करे और बताए कि केंद्र ने चावल खरीद कर कितना रुपया दिया और इस वर्ष कितना देने वाली है उन्होंने कहा केंद्र द्वारा दी जा रही राशि पर वाहवाही लूटना कांग्रेस की आदत बन चुकी है।

राज्य सरकार बार-बार झूठ कहती है कि धान का एक भी रुपया केंद्र नहीं देता जबकि विधानसभा में स्वयं वह स्वीकार कर चुकी है कि राज्य एक एजेंसी के रूप में ही धान की खरीदारी करता है यहां तक की मंत्री अमरजीत भगत ने तो विधानसभा में यह राशि भी बताई थी कांग्रेस में दम है तो आंकड़े जनता के सामने रखें।

केंद्र 1 किलो धान नहीं खरीदता -कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा धान खरीदी पर लगातार झूठ बोल रही है। भाजपा अध्यक्ष अरुण साव झूठ दावा कर रहे है कि केंद्र सरकार धान खरीदी का बारदाना, सुतली और ट्रांसपोर्टिंग तक का पैसा देती है। जबकि हकीकत यह है कि केंद्र सरकार 1 किलो भी धान की खरीदी नहीं करती है, राज्य सरकार अपने दम पर मार्कफेड के माध्यम से धान की खरीदी करती है। केंद्र का इसके एक रू. का भी योगदान नहीं है। केंद्र अपनी आवश्यकताओं के लिये राज्य से चावल खरीदता है। छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के कारण किसानों को देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत 2640 और 2660 रू. मिल रही है। केंद्र सरकार के अड़ंगेबाजी के कारण किसानों को धान की पूरी कीमत एक साथ नहीं मिल पाता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि किसानों को धान की कीमत 2640 और 2660 रू. जो मिला उसके पीछे कांग्रेस की राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। जिसके कारण किसानों को 9000 रू. प्रति एकड़ की इन्पुट सब्सिडी मिल रही है। इन्पुट सब्सिडी प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदी के हिसाब से 2040 रू. प्रति एकड़ होती है। 600 रू. और समर्थन मूल्य के 2040 तथा 2060 रू. का जोड़ मिलाकर किसानों को 2640 और 2660 रू. मिला है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की यह सहायता भाजपा के किसान विरोधी निर्णय के कारण ही शुरू की गयी। केंद्र सरकार रोक नहीं लगाती तो किसानों को कांग्रेस सरकार एकमुश्त भुगतान करती। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा की कथनी करनी का अंतर हमेशा से अलग रही। छत्तीसगढ़ में सरकार में रहते भाजपा ने वायदा किया कि धान का 2100 रूपये समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया। 5 साल तक 300 रूपये बोनस देंगे, 5 साल नही दिया। धान का एक-एक दाना खरीदेंगे, नहीं खरीदा। 10 क्विंटल खरीद रहे थे कांग्रेस के विरोध के बाद बढ़ाया। 2014 के चुनाव के पहले मोदी ने वायदा किया था स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों लागू करेंगे लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत जोंडकर समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करेंगे। 2022 बीत गया किसानों की आय बढ़ने के बजाये घट गयी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव में किसानों से केंद्र में भाजपा की सरकार बनने पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने,महंगाई कम करने, किसानों की आय दुगुनी करने का वादा किया था। लेकिन 2013 में बनी रमन सिंह की सरकार और 2014 में बनी मोदी की सरकार ने किसानों से वादाखिलाफी कर किसानों के साथ अन्याय किया।

स्मार्ट बिजली मीटर योजना का विरोध किया किसान सभा ने

- सरकार से अपील की है कि इस योजना को लागू न करें

रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने स्मार्ट बिजली मीटर योजना का विरोध किया है और कहा है कि यह बिजली क्षेत्र के निजीकरण और इसे अडानी को सौंपने की मुहिम का हिस्सा है। किसान सभा ने कांग्रेस की राज्य सरकार से अपील की है कि इस योजना को लागू न करें।

आज यहां जारी एक बयान में छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा है कि पूरे देश से आ रही रिपोर्टों से स्पष्ट है कि स्मार्ट मीटर की संरचना इस तरह डिज़ाइन की जा रही है कि वे डिजिटल मीटर से ज्यादा तेजी से चलते हैं और वास्तविक खपत से ज्यादा दर्ज करते हैं। इस प्रकार ये मीटर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त नाजायज बोझ डालने वाले साबित हो रहे हैं। अत: इन स्मार्ट मीटरों की उपयोगिता और उपादेयता संदेह के दायरे में है।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटरों को पहले

चार्ज कराना होगा। इससे स्पष्ट है कि जो गरीब पहले जेब से पैसे खर्च करने में असमर्थ होंगे, वे अंधेरे में रहने को मजबूर होंगे। इसके साथ ही बिजली की दरों को तय करने में नियामक आयोग की भूमिका खत्म हो जाएगी और बिजली दरों को कभी भी बढ़ाया जा सकेगा। इससे आम जनता की बदहाली और बढ़ेगी। इस प्रकार, यह योजना राज्य में अंधकार युग की दस्तक साबित होगी।

किसान सभा नेताओं ने कहा है कि हिन्डेनबर्ग रिपोर्ट से साफ है कि अपने मुनाफे के लिए अडानी किस तरह की व्यावसायिक जालसाजी कर रही है और आम जनता की जेब में डाका डाल रही है। छत्तीसगढ़ में बिजली क्षेत्र में अडानी का प्रवेश आम जनता के लिए संकट का कारण बनेगा। उत्तरप्रदेश के अनुभव से स्पष्ट है कि यदि अडानी को स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर मिलता है, तो राजस्व पर 2000 करोड़ रुपयों से अधिक का अतिरिक्त भार खजाने पर पड़ेगा, जो प्रकारांतर से आम जनता से ही वसूले जाएंगे।

किसान सभा ने कहा है कि बिजली राज्य का विषय है और केंद्र सरकार की इसमें दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जानी चाहिये, जिसका एकमात्र उद्देश्य बिजली क्षेत्र में निजीकरण की मुहिम को बढ़ाना और इसे अडानी जैसे लुटेरे कॉर्पोरेट को सौंपना है। इसलिए राज्य सरकार को स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पर रोक लगानी चाहिए, ताकि ऊर्जा संबंधी आम जनता की न्यूनतम जरूरतें पूरी होती रहे।

कांग्रेस महाधिवेशनः टेंट सिटी निर्माण का मुख्यमंत्री ने किया भूमिपूजन

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को नवा रायपुर में प्रस्तावित कांग्रेस महाधिवेशन स्थल पर टेंट सिटी निर्माण का भूमिपूजन किया। मेला ग्राउंड पर महाधिवेशन के लिए 13-14 हजार लोगों की बैठक क्षमता वाला भव्य डोम बनेगा। महाधिवेशन स्थल पर ही कांग्रेस के इतिहास पर केंद्रित एक प्रदर्शनी, राज्य सरकार की उपलब्धियों बताने वाले स्टाल और स्थानीय उत्पादों के बिक्री के लिए स्टाल भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को मंत्रियों और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ नवा रायपुर पहुंचे। वहां उन्होंने टेंट लगाने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों से बात कर पूरी योजना समझी। बाद में वहां नारियल फोड़कर पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने कहा, विचार, रणनीति और देश की दिशा निर्धारित करने के लिए आयोजित इस मंथन महायज्ञ से जनकल्याण और भारत जोडऩे का संकल्प और अधिक मजबूत होगा।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

छात्रों की मौत पीड़ादायक जिम्मेदार कौन-कौशिक

रायपुर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर कोरर में सड़क हादसे से हुए छात्रों के मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं ने सबको विचलित कर रखा है लेकिन हादसों पर अंकुश लगाने राज्य की कांग्रेस सरकार के पास अब तक कोई नीति नहीं है और न कोई तैयारी। भानुप्रतापपुर में सड़क दुर्घटना में स्कुली बच्चों की मौत हो गई। इस तरह की घटनाएं हर जिले में बढ़ते जा रही है, यातायात पुलिस का पता तो प्रदेश में पता ही नहीं। उन्होंने कहा कि इसके लिये सड़कों की दुर्दशा व यातायात व्यवस्था का दुरूस्त नहीं होना ही मूल रूप से जिम्मेदार है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि हादसों की एक ही वजह नशे की हालात में वाहन चलाना ही है जिसके लिये प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। जगह-जगह नशे का सामान उपलब्ध है। कांग्रेस सरकार इस पर कार्यवाही के बजाए शराब के हर तरह के धंधे को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि हर जिले में हर अनुविभाग में एक यातायात पुलिस उप अधीक्षक की नियुक्ती हो साथ ही यातायात पुलिस की जिम्मेदारी और तय की जाए ,जिससे की ऐसे हादसों रोका जा सके।

रमन सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का रिकार्ड बनाई : धनंजय

रायपुर। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने अपने अधिकृत फेसबुक प्रोफाइल से खुद के नाम से दूसरे प्रोफाइल बनाकर ठगी करने की सूचना दी और सचेत रहने की सलाह दी इस पर प्रतिक्रिया तंज कसते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रमन सरकार ने तो 15 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का रिकॉर्ड कायम किया है। पूर्व रमन सरकार का ही कोई प्रशंसक होगा जो रमन सिंह के नाम से फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर ठगी का प्रयास कर रहा होगा। रमन सिंह आप चिंता न करे प्रदेश की जनता 15 साल तक रमन सरकार की ठगी की शिकार थी वो अब सावधान है ऐसे किसी भी झांसे में नही आने वाली है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रमन सरकार के 15 साल के ठगी के कारनामे 20 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर गरीबों के चावल में घोटाला कर 36 हजार करोड़ के चावल चोरी कर प्रदेश के गरीबों को ठगे? युवाओं को 2003 में 500 रु. महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर ठगा, किसानों को धान की कीमत 2100 रु. प्रति क्विंटल और 300 रु. बोनस देने का वादा कर ठगा, आदिवासी वर्ग को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय एवं उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा कर ठगा। रमन सरकार के 15 साल के शासनकाल में हर वर्ग ठगी के शिकार हुये।

झीरम मामले में कांग्रेस छिपा रही तथ्य, अपराधी के चेहरे आए सामने -रमन सिंह

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने झीरम घाटी मामले में हो रही जांच और अडाणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लग रहे आरोपों पर भी बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में झीरम कांड को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ। रमन सिंह ने राजनांदगांव में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के झीरम घाटी एनआईए की जांच के मामले को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया है। रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। असली चेहरा सामने आना चाहिए = रमन सिंह ने झीरम घाटी मामले में मुख्यमंत्री के बयान को लेकर कहा कि %%इतने दिन बीतने के बाद केंद्र में उनके प्रधानमंत्री थे। सोनिया गांधी,राहुल गांधी यहां आये थे। जांच एजेंसी भी उनके द्वारा ही तय की गई। हमने तय नहीं किया। छत्तीसगढ़ का बच्चा-बच्चा जानता है कि यह कांग्रेस के अंतर्कलह का परिणाम है। जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। कांग्रेस जांच में सहयोग करे।

झीरम आयोग के कार्यकाल बढ़ाने पर भाजपा तिलमिला क्यों रही? - कांग्रेस

रायपुर। जीरम न्यायिक आयोग के कार्यकाल को बढ़ाये जाने के निर्णय पर भाजपा द्वारा की जा रही बयानबाजी को कांग्रेस ने अवांक्षित और अमर्यादित बताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा जांच को बाधित करना चाहती है। जीरम न्यायिक आयोग की जांच पर रोक का पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक स्टे लेकर रखे है। भाजपा डरती है जीरम का सच सामने आ जायेगा तो वह बेनकाब हो जायेगी। रमन सिंह से बड़ा क्रूर शासक आजाद भारत में आज तक नहीं हुआ। एक साथ विपक्ष के 32 नेताओं की हत्या हो गयी और तत्कालीन सरकार सच सामने आने देने से रोकने में पूरी ताकत लगा रखी थी। भाजपा के बड़े नेता जीरम की जांच को रोकने लगातार कोशिशें कर रहे उसमें साफ हो रहा जीरम के पीछे तत्कालीन भाजपा सरकार की भूमिका संदिग्ध है। जीरम आयोग के कार्यकाल बढ़ाने पर भाजपा तिलमिला क्यो रही है? पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक द्वारा हाईकोर्ट से स्टे लिये जाने के कारण आयोग का कार्यकाल बढ़ाये जाने के बाद जांच शुरू नहीं हो पाई है फिर से आयोग का कार्यकाल बढ़ाना पड़ा।

कांग्रेस झीरम घाटी की जांच पूरी होने नही दे रही केवल राजनीति कर रही- चंद्राकर

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व राज्य शासन के पूर्व वरिष्ठ मंत्री अजय चंद्राकर ने झीरम घाटी कांड न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल 6 माह बढ़ाये जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि झीरम का सच सबके सामने है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जांच आयोग बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। झीरम कांड के प्रत्यक्षदर्शी कवासी लखमा तो उनकी सरकार में मंत्री हैं। भूपेश बघेल उनसे पूछ लें। वे जिसका नाम लें, भूपेश उसे फांसी पर लटकवा दें। कवासी लखमा से तो रोज पूछताछ होनी चाहिए। झीरम के पीड़ितों को चार साल में क्या मिला? प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता पूर्व मंत्री व वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि जांच आयोग बनाने की जरूरत नहीं थी लेकिन कांग्रेस को राजनीति करनी है। उन्होंने भूपेश बघेल सरकार द्वारा बनाई गई कमेटियों के औचित्य पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इतनी कमेटी बनाई, कई जांच आयोग बनाए, उनमें से किसी की भी जांच रिपोर्ट नहीं आई। उन्होंने कहा कि क्या शराबबंदी कमेटियों की रिपोर्ट आई, क्या स्काईवॉक कमेटियों की रिपोर्ट आई, क्या भूपेश बघेल सरकार द्वारा गठित झीरम जांच आयोग की रिपोर्ट आई? जब प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस सरकार में मंत्री है तो उनसे ही पूछ लें कि सच क्या है। हो गई जांच और क्या।

स्वच्छता में रायपुर को शीर्ष पर लाने नगर निगम ने शुरू की मुहिम

रायपुर। स्वच्छतम शहर के तौर पर रायपुर की रैंकिंग को शीर्ष पर लाने नगर निगम, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और अन्य उपक्रमों के साथ मिलकर आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ा रहा है। घर, प्रतिष्ठान व संस्थानों से निकलने वाले कचरे के पृथक्करण पर जोर देते हुए जन जागरूकता के माध्यम से सूखे एवं गीले कचरे को पृथक कर ही कचरा संग्रहण वाहनों में देने की समझाइश देकर इसकी शुरुआत की गई है।

रायपुर नगर निगम कमिश्नर मयंक चतुर्वेदी के अनुसार हर घर से कचरे के पृथक्करण के अभियान की शुरूआत हो चुकी है। डोर-टू-डोर संपर्क कर स्वच्छता अपनाने के लिए हर घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान व संस्थानों को प्रेरित किया जा रहा है। छोटी गुमटियों से लेकर बड़े होटल, मोहल्ले के घरों और कॉलोनियों को भी कचरे के पृथक्करण के लिए निरंतर समझाईश दी जा रही हैं। जोन स्तर पर स्व-सहायता समूहों व स्वच्छता दीदियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि निरंतर लोगों को इस संबंध में अवगत कराएं, इस हेतु प्रत्येक जोन स्तर पर 15 महिलाओं को दायित्व सौंपा गया है, जो लापरवाही बरतने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगी। रेलवे सहित अन्य सार्वजनिक व व्यापरिक उपक्रम भी स्वच्छतम रायपुर के मिशन में नगर निगम को साथ दें रहे है।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में किया आधुनिक अनुसंधान तकनीकों का अवलोकन

छत्तीसगढ़ के शोधार्थी एवं वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान

रायपुर। अब छत्तीसगढ़ में शोध कार्य कर रहे शोधार्थी और वैज्ञानिको को अब अंतर्राष्ट्रीय चांवल अनुसंधान मनीला फिलीपिंस में अनुसंधान और शोध करने की सुविधा भी मिलेगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार, इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय और मनीला के अंतर्राष्ट्रीय चांवल अनुसंधान संस्थान में समझौता हुआ है। समझौते के तहत इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर तथा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला के बीच एक त्रिपक्षीय आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेन्ट) पर हस्ताक्षर किए गए। उल्लेखनीय है कि कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने पिछले दिनों फिलीपिंस के मनीला स्थित अंतर्राष्ट्रीय चांवल अनुसंधान केन्द्र का भ्रमण पर थे। इस अवसर पर यह समझौता किया गया। डॉ. कमलप्रीत ने वहां स्पीड ब्रीडिंग कार्यक्रम का जायजा लिया।

डॉ. कमलप्रीत ने अनुसंधान संस्थान में विकसित किए जा रहे धान की नई किस्मों और अनुसंधान के बारे में वहां के वैज्ञानिकों से चर्चा की और आधुनिक तकनीकों की जानकारी ली। कृषि उत्पादन आयुक्त के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की कृषि विभाग की टीम ने मनीला के वैज्ञानिकों को छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और कार्यक्रमों के साथ ही नरवा, गरूवा, घुरवा, और बाड़ी कार्यक्रम और गोधन न्याय योजना की विस्तार से जानकारी दी। जिसे अनुसंधान संस्थान मनीला के वैज्ञानिकों द्वारा सराहना की गई।

मनीला गए छत्तीसगढ़ की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में विश्व के सबसे बड़े धान जर्मप्लाज्म संग्रह में वहां 100 साल से अधिक समय के लिए संग्रहित धान की एक लाख 30 हजार से अधिक किस्मों का भी अवलोकन किया। कृषि उत्पादन आयुक्त ने इस तकनीक को कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अपनाकर छत्तीसगढ़ में धान की नवीन किस्मों के विकास में तेजी लाने, उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने पर जोर दिया। कृषि उत्पादन आयुक्त की अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई चर्चा में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि छत्तीसगढ़ में धान की नवीन प्रजातियों के विकास हेतु धान अनुसंधान की नवीन तकनीकों के उपयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कार्य करेगा। इस मौके पर इंदिरागांधी विश्व विद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, आई आर आर आई के प्रजनन कार्यक्रम आधुनिकीकरण प्रमुख डॉ. संजय के. कटियार भी उनके साथ थे।

आर.एन.आई. रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.